[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

लिफ्ट (सिंचाई) योजनाएं 60 मीटर लिफ्ट तक एवं सागर मल गोपा को बाड़मेर जिले के गढ़त रोड तक बढ़ाने का निर्णय जून, 1983 में ले लिया है। पेयजल व उद्योगों के लिए भी पानी की आरक्षण मात्रा 500 क्यूसेक से बढ़ाकर 1200 क्यूसेक कर दी है। जिसे 2000 क्यूसेक तक बढ़ाना आवश्यक है।

• अत: राज्य सरकार केन्द्र सरकार के सहयोग से राजस्थान नहर द्वारा रेगिस्तानी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर एवं चुरू जिलों में जहां पानी का भयकर संकट है, के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तक भी पानी पहुंचाया जा सकता है, वहां और उक्त जिलों के महत्वपूर्ण नगरों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, शेरगढ़, पोकरण, नागौर बाजोतरा में तुरंत से तुरंत योजनाएं बनाकर सातवीं पंचवर्षीय योजना में पानी उपलब्ध कराकर मरू क्षेत्र की जनता की आवश्यक मांग की पूर्ति कर स्थायी हल का समाधान करे।

14 57 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: TEXTILE UNDERSTANDINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) ORDINANCE AND TEXTILE UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL— Contd.

MR. CHAIRMAN : Now the House will take up items 8 and 9 together for further consideration.

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, मैं कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) विधेयक, 1983 जो माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

यह विधेयक जिन परिस्थितियों में इस सदन में आया है, वह अपने आप में कपड़ा उद्योग में खास तौर से एक इतिहास बनाने वाला है। सदन को मालूम है कि कपड़ा उद्योग का मजदूर किसी न किसी भुलावे में आकर गलत तरीके से तत्वों के हाथों में बीस महीने तक काम करता रहा है, जो मिल-मालिकों से मिले हुए थे। डा० दत्ता सामंत ने कभी मजदूरों के हित के बारे में नहीं सोचा और न कभी सोचते थे। मजदूरों को बर्बाद करने के लिए और अपनी हठधर्मी के कारण बीस महीने तक इस मिल को चलाया, जिससे राष्ट्र का उत्पादन गिरा। इस के साथ साथ 35 हजार मजदूर रोजी-रोटी के लिए 20 महीने के लिए मोहताज हो गए। यही नहीं जिन 13 मिलों का अधिग्रहण किया जा रहा है, इनमें अधिग्रहण से पूर्व अगस्त 1983 में इनका उत्पादन 20 प्रतिशत था, जबकि दूसरी मिलों में कपड़े का उत्पादन उसी महीने में 77 प्रतिशत था। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इन मिलों की क्या हालत है। जब इस तरह से उत्पादन में गिरावट हो तो वह राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के उत्पादन में एक बहुत बड़ी क्षति थी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार नहीं की जा सकती है।

14.59 hrs.

(SHRI N.K. SHEJWALKAR *in the Chair*)

मान्यवर, यही नहीं, माननीय मंत्री जी

के पास उनके द्वारा किए गए वैरिफिकेशन की रिपोर्ट है, बैलेंसशीट हैं, जिससे आपको मालूम होगा कि इन मिलों को जो आधुनिकीकरण के लिए पैसा दिया गया था, वह उन्होंने व्यक्तिगत कामों में या दूसरे उपक्रमों में उस पैसे को लगा लिया है । इस प्रकार से जानबूझकर मिल-मालिकों ने मिलों के उत्पादन को गिराया। जिससे मिलों की स्थिति खराब होती जा रही थी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं रोटी-कपड़ा मकान—ये तीन न्यूनतम आवश्यकताएं मजदूरों की हैं। कपड़े के संबंध में जितनी भी मिलें देश के अन्दर चल रही हैं, उनमें 34 मिलें घाटे में चल रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास इंडस्ट्रीयल डवेलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट है और इस रेगुलेशन एक्ट के तहत आप को यह अधिकार दिया हुआ है कि ऐसी मिलो के बारे मे जब भी आपको सूचना आती है तो आप उसके बारे में स्टडी ग्रुप कायम कर सकते हैं या इंक्वायरी बैठा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इण्डस्ट्रीयल डवेलपमेंट रेगुलेशंज एक्ट के अन्तर्गत उन 34 मिलों के विरुद्ध भी एन्क्वायरी बैठाइये ताकि पता लग सके कि इन मिलों में हमारे देश का जो पैसा लगा हुआ है किस कारण से उन का उत्पादन गिर रहा है, हमारे जो ऐसेटेस हैं उन का भी नुकसान हो रहा है।

मुझे यह भी मालूम हुआ है कि जिस समय आप ने इन मिलों का अधिग्रहण किया इन में से कुछ मिलों की बैलेंस शीट्स और एकाउंट्स से संबधित कागजात नहीं मिले। क्या ऐसा हो सकता है कि उन की बैलेंसशीट उपलब्ध न हो या उन के एकाउन्ट्स उपलब्ध न हों? मैं चाहता हूं कि ऐसी मिलों के बारे में जहां ये चीजें उपलब्ध नहीं हुई हैं, उन के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें ताकि उन के बारे में सही आंकड़े उपलब्ध हो सके।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति कोई मिल लगाता है तो अधिक से अधिक भूमि का अधिग्रहण करता है। इन मिलों के पास भी बहुत काफी सरप्लस लेंड है जिन की बाजारू कीमत करीब 163 करोड़ रुपये है। मंत्री जी, आप को मालूम है कि कोहिनूर मिल के मालिकों ने, जब वे बकाये का और विभिन्न टैक्सों का भुगतान नहीं कर सके और उन के पास नोटिस गये तो उन्होंने अपनी सरप्लस लैंड को बेचने की अनुमति मांगी थी। इस लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन मिलों के पास जो सरप्लस लैंड है उस को बाजार भाव पर बेच कर आगे चलाने के लिए जिस रुपये की आवश्यकता है, माडर्नाइजेशन के लिए जितने रुपये की आवश्यकता है, मजदूरों का जो बकाया है, उन के भुगतान के लिये आप इस रुपये का इस्तेमाल करें। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि इन मिलों के माडर्नाइजेशन के लिये फाइनेन्शियल इंस्टीचूशंज से यह उम्मीद की जाती है 140 करोड़ रुपये के लगभग प्राप्त हो सकेगा। इस लिए यह सदन आपसे आशा करता है कि सरप्लस लैंड को बेच कर तथा वित्तीय संस्थाओं से जो रुपया मिल सकता है उस को प्राप्त कर के जो मेरे अनुमान के अनुसार 300 करोड़ से अधिक होता है, इन मिलों के मार्डनाइजेशन में लगाएंगे। मार्डनाइजेशन करने से जहां एक तरफ जो रुपया उन में पहले से लगा हुआ है, बैंक का रुपया या दूसरी संस्थाओं का रुपया लगा हुआ है, उस को बचा सकेंगे साथ ही देश का उत्पादन बढ़ेगा और मजदूरों का भी भला हो सकेगा।

[श्री राम सिंह यादव]

माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने इस संबंध में अभी तक जो प्रयत्न किये हैं वे अपने आप में बहुत प्रशंसनीय हैं। इन मिलों के अधिग्रहण के पश्चात यह साबित हो चुका है कि डा० दत्ता सामंत यह चाहता था कि ये मिलें न चलें और मिल मालिक भी यही चाहते थे कि ये मिलें न चलें। अधिग्रहण के बाद मालूम हुआ कि दोनों मिले हुए हैं और उन का उद्देश्य मजदूर वर्ग को नुकसान पहुंचाना था, वे राष्ट्र के उत्पादन को गिराना चाहते थे। मिल मालिकों ने अधिग्रहण के पश्चात हाई कोर्ट में जो रिट दायर की है कि मिलों का अधिग्रहण न किया जाय, वे एक तरफ तो यह कहते थे कि उत्पादन गिर रहा है, हमारे पास नहीं है, हम को सरप्लस लैंड को बेचने की अनुमति दी जाय, लेकिन दूसरी तरफ वे अधिग्रहण के खिलाफ रिट दायर करते हैं। जहां तक मुझे मालूम है बम्बई हाई कोर्ट में उन्होंने जो रिट दायर की थी, वह खारिज हो चुकी है। इस लिये मेरा निवेदन है कि आप ने जिस तेजी के साथ इन मिलों को अधिग्रहण किया है, इन का मार्डनाइजेशन भी किया जाय जिस से इन की स्थिति में सुधार हो सके। यदि आप ने ऐसा नहीं किया तो जिस तरह एन० टी० सी० को 111 मिलें घाटे में चल रही हैं और वह घाटा 426 करोड़ रुपये पर पहुंच चुका है, उसी तरह से इन मिलों में भी घाटे की स्थिति पैदा हो सकती है। हमें ऐसा रास्ता अपनाना चाहिये जिस से ये मिलें अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के साथ कम्पीटीशन में स्टेण्ड हो सकें।

हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने एक बहुत ही साहसिक कदम यह उठाया है कि उन्होंने एक्सपोर्ट के लिये नये एवेन्यूज खोले हैं। इस से हमारे वस्त्र उद्योग को बहुत उत्साह मिलेगा। आप का यह कदम बहुत प्रशंसनीय है, इस काम से हमारे वस्त्र उद्योग की जो मिलें हैं, जिन में एन० टी० सी० की मिलें भी शामिल हैं, उन में घाटा हो रहा था उस की पूर्ति हो सकेगी। इन में हमारे जो मजदूर काम कर रहे हैं उन के हालात बेहतर हो सकेंगे और उन की बेहतरी के लिए आप और अधिक ठोस कदम उठा सकेंगे। जस्टिस वी०डी० देशपांडे की अध्यक्षता में जो कमेटी मुकर्रर की गई है उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि मजदूरों को हाउस रेंट अलाउंस दिया जाय। कुछ मिलों ने इसकी घोषणा की है, लेकिन अन्य प्राइवेट सैक्टर की क्या दूसरी मिलें जो नहीं दे रही हैं उसके बारे में आप ठोस कदम उठायें ताकि मजदूरों को एच० आर० ए० मिले। जस्टिस वी० डी० देशपांडे कमेटी की फाइनल रिपोर्ट प्राप्त होने का है, मैं चाहूंगा कि आप उसे शीघ्र प्राप्त करें क्योंकि उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में हैं कि किस तरह से वेजेज को बढ़ाया जाय और संतुलित किया जाय। कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों में ब्रोनकाईटिस और टी० बी० अधिक होती है इस को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि उन मजदूरों को अधिक प्रोत्साहन दें, और यह तभी सम्भव हो सकता है कि यूनीफार्म तरीके से सभी मजदूरों के मामले को डील करें। इसलिए उस कमेटी की अंतिम रिपोर्ट ले कर शीघ्र ही आप ठोस कदम उठायें।

आपने जो सस्ता कपड़ा गरीब आदमी को देने की व्यवस्था की है जिसके कारण

एन० टी० सी० मिलों को घाटा हो रहा है वह कपड़ा सही तरीके से उन्हीं लोगों को मिले जिनके लिये बनता है इस बात की आपको मजबूत व्यवस्था करनी होगी। अभी आप कंज्यूमर्स स्टोर्स के माध्यम से उस कपड़े को बेचते हैं। मेरी मांग । लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आपकी अपनी दुकानें हों जहां वह कपड़ा बेचा जाय ताकि बिचौलिये उसको न ले सकें और ब्लेक मार्केटिंग न कर सकें, और वह कपड़ा आम आदमी को ही मिले। इसलिये उसके बेचने की समुचित व्यवस्था अभी नहीं है । हमने फील्ड में देखा है कि यह सस्ता कपड़ा उनको नहीं मिलता है जिनके लिये बनाया जाता है। अखबारों में भी ऐसी खबरें आयी हैं।

पी० यू० सी० ने सुझाव दिया है, अपनी 40 वीं रिपोर्ट में कहा है कि एन० टी० सी० को प्राइवेट सेक्टर से कम्पीट करने के लिए वित्तीय साधनों के अनुसार उनका मार्डनाईजेशन किया जाय, साथ ही फैब्रिक ब्लंड को माडर्न तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए।

> "The Committee would suggest that while taking-up modernisation on a selective basis priority should be assig ned to instal the balancing equipment badly needed by the mills. Efforts should be concentrated on mills that are making continuously heavy losses, mills that could be commission their installed capacity and mills whose available spindles capacity is not of economic size. However, the Committee do not rule out the need for modernising selected profit making in mills to take up production of blended fabric or otherwise, to improve the quality of the products to make them competitive and to make NTC breakeven on the whole early. Incidentally, the Committee would urge that rennovation of factory buildings, which are very old and dilapidated and hence a potential threat to the safety of the workers, should be attended to with a sense of urgency."

कमेटी की यह सही राय आपकी एन० टी० सी० की वर्किंग में सहायक सिद्ध होगी । आधुनिकीकरण के मुद्दे को अधिक प्राथमिकता देंगे, यही मुझे निवेदन करना है ।

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly): Mr. Chairman, Sir, we had been repeatedly demanding nationalisation of the entire textile industry for a long time.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): This is your slogan.

PROF. RUP CHAND PAL: This demand was there from our side even in 1974 when the take over of others had taken place.

The textile industry, as you know, is one of the most important industries and is the largest industry in our country. Cloth is one of the essential commodities for the common people. It has also got export potential. But because of continuous mismanagement, corruption, siphoning of money provided by public financial institutions and banks, this textile industry has been deliberately made to grow sick. We had given specific instances naming the mills where these activities were going on, and where they were diverting money and mismanaging things in such a way that corruption is rampant. But nothing has happened. Still, although it has come very belatedly, we welcome the Government's move.

I am not commenting on the timing of the announcement i.e. during the time of the AICC session, the announcement was made. I am not commenting on whether it was done with an eye on the elections, i.e. on the votes of the textile workers,

[Prof. Rup Chand Pal]

particularly in North Bombay. But will this take-over of the 13 mills solve the problem ? That is my simple question. It will not. (*Interruptions*) It may be that you wanted to strengthen the Rashtriya Mill Mazdoor Sangh, your INTUC union which is quite isolated. But it will not solve the problem.

Over the years, you have taken steps which have only helped these unscrupulous people who have been engaged in loot. Loot is the word I am using. That is the only word we should use. What is happening, apart from this loot ? Out of 12 lakh textile workers, how many are getting jobs ?

I am speaking from your statistics. Not more than 7 lakhs. Five lakhs of textile workers do not get regular jobs. They are either *badlis* or extra or temporary, whatever name you may give them.

Look at the capacity utilization. Out of 723 textile mills, according to your statistics, 57 have not provided any data. May be, they are producing only staple fibre. Only 583 are working in three shifts; only eleven in two shifts; only nine in one shift; and 63 mills were closed before the beginning of this Bombay textile strike.

Now what is the position ? How many mills are closed ? How many of them are big ? Look at Kanpur. Look at the big unit of Modis. Look at Faridabad. Look at Delhi itself. There is one Birla textile mill, where there are 6,000 workers, and they have declared 3,000 surplus.

You are not able to utilize the capacity. (*Interruptions*) I will come to my State. The workers are not getting their share. Look at Bombay itself. In Bombay, before the strike, we had 225,000 workers. How many of them are getting jobs after this pious announcement during the AICC session ? Not more than 1.5 lakhs. That means, till to-day more than 75,000 workers are out of employment.

Another aspect. You look at the working of these textile mills. What is happening ? They are trying to shirk the responsibility of weaving. They are leaving it to the powerlooms. The spinning part they do. For handlooms, there are concessions. If it is four or less than that, no excise duty. So, Birlas and Tatas also have switched over to powerlooms producing cloth there and have come back again to the most profitable part, the processing section. That is a lacuna in the industry itself.

The big monopoly houses are exploiting all these things. They are not only looting the public financial institutions and exploiting the workers ruthlessly but also their PF money is not deposited. ESI money is being swallowed up. How is it going to solve the problem ?

Look at the nationalised sector. NTC is carrying forward loss to the tune of more than Rs. 426 crores and it is incurring loss continuously. Why ? It is a nationalised sector. There is not only mismanagement but also corruption. There was one Managing-Director who was Moosa Raza or something like that. There was a concrete proof of corruption against the Managing-Director of NTC. What has happened to him ? What is the attitude of the Government ? Will the hon. Minister in his reply tell us what has happened to that person ? Did this government give him another assignment ? They have exonerated him of all the corruption charges.

In West Bengal, all the CITU unions under the NTC mills had met the Managing Director, part-time Mr. Billimoria and suggestions had been given: these were the cases of mismanagement and these were the spheres of corruption, you could make a market survey; if necessary, you could go to some other production and we believe that we shall be able to

make all these units viable." Two years have passed. The Managing-Director has agreed that their suggestions are 100 per cent correct. So far nothing has come out. This is the nationalised sector. I am replying to you, Mr. Vyas. You know, they have set up a committee.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS (Bhilwara) : I know better than you.

PROF. RUP CHAND PAL : No, you do not know. Why have these 13 mills been taken over.—at the AICC session with an eye to the electorate ? Should we not call it a gimmick when there is a committee which is looking into the 26 mills and their operation ? It is being said that these 26 mills are not viable and they are going to be closed down. That is the study of the NTC; and 12 of them are in West Bengal. That is your nationalised sector.

Government has come out regarding sickness. More than 80 per cent of the sickness is due to mismanagement. That is their statistics. While replying to the debate, I want to know about the position of the NTC, whether it is correct or not that 26 units are going to be closed down.

Regarding controlled cloth, why only NTC would be allowed to do it ? Why not others ? What do they do ? This is a small responsibility. They think that paying penalty is cheaper than producing this controlled cloth. That is this government's measure that they pay penalty without taking this responsibility.

It is being said that Tatas and Birlas and others have been engaged in the textile industry and they are great foreign exchange earners. It is so ? They are squandering away money from the public financial institutions; they are squandering away our foreign exchange; and on the other hand, they are enjoying all the concessions given by this government.

There is one provision called import entitlement. That is, if you export, you are entitled to import some-thing. They are importing foreign machinery and as a result, some of our items of machinery are lying idle. Ours are not out-dated items of machinery, they are also capable of producing as well as the foreign machinery. I had occasion to visit one of them, and found that they are sitting idle. And because of this import entitlement these monopolists are able to import all sorts of machinery into the country.

What was the result of the study made by the Reserve Bank of India about 10 years ago ? It was found that these people are spending more foreign exchange than they are earning through exports. Will the Government institute an enquiry to find out how much foreign exchange they have earned and how much they spent on claims towards their travelling allowance, and daily allowance spent for their executives in foreign countries. There has been a study and it shows that these monopoly houses have spent more money in terms of foreign exchange than they have earned.

So, our plea is that nothing short of nationalisation can solve the problem of this textile industry. Nothing short of complete nationalisation. If you do not do it, today I do not have to tell you what is going to happen. The interim period between the taking over and nationalisation will be fittered away and it will benefit the same people, like Musharadi. The bureaucrats are also involved in this. All the aid given by the financial institutions is taken away by these monopolists. How can you say that by taking over all. these 13 mills the problems of the Textile industry will be solved ? It can never be done. This can be done only by overhauling the NTC. or by taking over or nationalisation of the entire textile industry and by ensuring the full participation of the workers in the management.

While the workers should be rewarded and praised whenever they come out with

[Prof. Rup Chand Pal]

cases of corruption, they have been punished. You know, that a Bill is pending in the House, called the public Financial Institutions Fidelity and Secrecy Bill. It will cover all these Government companies. If any employee divulges anything in writing, there will be punishment. What has happened? Hundreds of crores of rupees have been spent away. Who can believe that a Tata mill can become sick? When the Tatas are amassing wealth, making fabulous profits they can hardly say that any textile mill will become sick. So, my plea will be that the entire textile industry will have to be immediately nationalised. Not only cotton, but jute also should be nationalised. Because jute is included in textile in your nomenclature, under your discretion. So, our demand will be that the entire textile industry will have to be nationalised. A new dialogue will have to be started. The workers and the management will have to work together and workers' participation will have to be assured.

And my last suggestion is that these specific demands should be recognised. I am not talking of any multi-nationals because I do not have much time. What I want to know is, why is the Government not taking any steps like nationalisation of the textile industry? You know the whole story. The world's largest textile magnate a U.K. based firm is seeking collaboration with the Modis. That means multinationals will flood us. That will loot us. Another phase of looting will begin. If the Government is sincere, the entire textile industry will have to be nationalised and the workers' participation will have to be ensured.

In Bombay you have made one announcement. Now you are going to hold your plenary session in Calcutta. Why not announce nationalisation of the jute industry. Plenty of them are lying closed today.

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं वाणिज्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करके एक बहुत ही साहसिक काम किया है। हालांकि हम लोगों को और पूरे देश को बड़ी प्रसन्नता होती यदि वे सभी कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देते।

सभी कपडा मिलों का राष्ट्रीयकरण ओवरड्यू है। कपड़ा उद्योग हमारे देश का बहुत पुराना उद्योग है। इसमें आज भी एक करोड़ से अधिक लोंग काम में लगे हुए हैं। लेकिन एक तरफ जहां मिलों की मिलें बीमार पड़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी मिलें ऐसी हैं, जो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रही है। जब मैं कपड़ा उद्योग की बात करता हूं, तो केवल कॉटन क्लोथ, सूती कपड़े की बात नहीं करता, बल्कि उसमें टेरीकॉट, टेरीवायल, सिंथेटिक फाइबर्स इत्यादि की भी बात करता हूं। एक तरफ ग्वालियर, रेआन, फगवाड़ा, जयपुर उद्योग, डी० सी० एम०, मफतलाल और भीलवाड़ा जैसे बड़े-बड़े उद्योग, जो ज्यादा मुनाफा कमा रहें हैं, वही दूसरी और ऐसे उद्योग भी हैं, जो कम मुनाफा कमा रहे हैं।

सभापति जी, सरकार ने कोई अस्पताल नही खोल रखा है, जो मिलें बीमार पड़ती जायें, वे उस अस्पताल में दाखिल होती रहें और लगातार उनकी दवादारू की जाती रहे। जो तन्दरुस्त हैं, वे आराम से घूमती रहें, तो जो घाटा राष्ट्रीयकरण की गई मिलों का है, वह तो बढ़ता ही रहेगा। आप दो-चार-दस मरीज को ठीक करें और फिर दो-चार-दस मरीज उसमें दाखिल हो जाएंगे। इस प्रकार लेखा-जोखा सारा

बराबर हो जाएगा। मेरी दृष्टि में सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए, जिससे समूचे वस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए। जिससे जो ज्यादा मुनाफे वाली मिलें हैं, वे भी सरकार के पास रहें और उनकी कमाई से बीमार मिलों को चलाया जा सके। उनका घाटा भी पूरा हो सके।

बम्बई में 13 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया है और समाचार पत्रों में यह खबरें बराबर छप रही है कि और 20-22 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना है। इस बारे में मंत्री जी को पता है कि उनको क्या करना है, यह उनका काम है। इस तरह से और मिलों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा तो अब समय आ गया है कि सरकार को सारे के सारे कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए।

सभापति जी आज कपड़ा उद्योग बहुत संकट से गुजर रहा है यह हम बराबर सुनते आ रहे हैं। बहुत सी मिलें बन्द होती जा रही हैं—सरकार को भी बराबर मिलों का अधिग्रहण करना पड़ रहा है। अखबारों में भी कई प्रकार की खबरें निकलतीं हैं—कहा जा रहा है कि बहुत सी मिलें पुरानी हो गई हैं उन का माडर्नाईजेशन नहीं किया जा रहा है और उन से पैसा मिल-मालिकों ने कमाया है, वह दूसरे उद्योगों में लगाते जा रहे हैं। फाइनेन्शियल इंस्टीचूशंज का पैसा ले कर जब तक मिल चलती है, वे चलाते हैं, अन्यथा बंद कर देते हैं और इंतजार में रहते हैं कि सरकार उन को अपने कब्जे में ले लेगी तथा उन को कुछ मुआवजा मिल जायेगा।

दूसरा कारण यह भी हो सकता कि हमारा वस्त्र उद्योग बहुत ही घटिया किस्म का कपड़ा बना रहा है जिस से बाहर के बाजारों में उस की खपत नहीं हो रही है। एक समय था—10-12 साल पहले शहर के बाजारों में हमारा कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा में जाया करता था और उससे हम विदेशी मुद्रा कमाते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि यूरोपीय देशों में या अमरीका में जो कोटे का सिस्टम है उस कोटे के मुताबिक भी हम अपने कपड़े को नहीं भेज पा रहे हैं। यूरोपीय देश का जो कोटा मिलता है उस का 25 परसेन्ट भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और इसी तरह से अमरीका का जितना कोटा मिलता है उस का केवल 13 प्रतिशत ही इस्तेमाल कर पाते हैं। इस का एक मुख्य कारण यह है कि हमारा कपड़ा विश्व के बाजार में बहुत घटिया है, विश्व के मार्केट में हम उस को कम्पीट नहीं कर सके हैं। इस लिये आप के माध्यम से मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि इस बात की जांच के लिये आप कोई कमेटी या कमीशन बैठायें जो इस बात का पता लगाये कि हमारा वस्त्र उद्योग किस प्रकार के संकट से गुजर रहा है और उस को इस संकट से उबारने के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है। यह इस लिये भी जरूरी है कि आज हमारे वस्त्र उद्योग में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं—एक करोड़ से ज्यादा लोग इस उद्योग में कार्यरत हैं और जहां कहीं भी ये मिलें बंद हो जाती हैं, चाहे कपड़ा मिलें हों या जूट मिलें हों, हजारों की संख्या में हमारे मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। इस लिये सरकार को इन के बारे में कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी ताकि रोजाना के इस झंझट से बचा जा सके और जैसा मैंने बतलाया

[श्री जैनुल बशर]

है—इस का एक ही उपाय है कि समूचे वस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तथा उसके बाद इस को ठीक प्रकार से चलाया जाय। एन० टी० सी० मिलों में जो घाटा बढ़ता जा रहा है, यह बहुत चिंता का विषय है। हमारे वाणिज्य मंत्री जी एक बहुत साहसिक आदमी हैं, योग्य हैं कर्मठ हैं, हर समय अपने काम में जुटे रहते हैं, इन के बहुत बड़े प्रयासों के बावजूद यह घाटा कम तो हो सकता लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि समाप्त नहीं हो सकता है । मैं उन की बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वे इस घाटे को प्राफिट में बदलने में समर्थ हो सकेंगे, अगर वह ऐसा कर सके तो वास्तव में वह एक "अजूबा" होगा यूं तो दुनिया में बहुत से अजूबे होते रहते हैं, फिर भी मुझे तो इस तरह की कोई आशा दिखाई नहीं देती है।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं—हमारे वस्त्र उद्योग से अक्सर इस बात की शिकायत मिलती है कि उन को पावरलूम्ज का मुकाबला करना पड़ता है । हैंडलूम्ज को मिलों के कपड़ों से प्रोटेक्शन चाहिये और अब मिलें पावर लूम्ज से प्रोटेक्शन मांग रही हैं। उन का कहना है कि पावर लूम्ज पर एक्साइज ड्यूटी और दूसरे प्रकार के टैक्स नहीं लगते हैं जब कि टैक्सटाइल मिलों पर बहुत से टैक्स लगते हैं जिस की वजह से उन को घाटा होता है। आज पावर लूम्ज देश में दिन प्रति दिन फैलते जा रहे हैं। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पावर लूम्ज के सूती वस्त्र उद्योग को, विशेषकर सिल्क वस्त्र उद्योग को खतरा पैदा हो रहा है उन को प्रोटेक्शन चाहिए।

सभापति जी, इस बात का मंत्री जी को पता लगाना चाहिए। और अगर ऐसा है तो कौन सा कपड़ा पावरलूम के जरिये बने और कौन कपड़ा मिलों के जरिये बने इस बारे में एक ठोस नीति निर्धारित की जानी चाहिये और उस पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिये।

PROF. N. G. RANGA (Guntur) : What about handlooms ?

श्री जैनुल बशर : हैंडलूम को तो प्रोटेक्शन चाहिये ही। आज पावरलूम हैंडलूम को तो खा ही रहा है, लगता है कि मिलों को भी खा जाएगा। यह ठीक है कि पावरलूम लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, इस बात को हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार को कोशिश करनी चाहिये कि कौन सी चीज हैंडलूम के जरिये बनाई जाय, कौन सी मिल के जरिये और कौन सी पावरलूम के जरिये, इस बात को तय किया जाय और ओवरलेपिंग न हो। इस प्रकार की एक ठोस नीति होनी चाहिये और सख्ती से उस पर अमल होना चाहिये।

मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि पूरे वस्त्र उद्योग को, चाहे टैरीकाट, टैरीवूल या सिन्थेटिक फाइबर हो या जूट मिलें हों, इन सब का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये, क्योंकि अब दोहरी नीति से नुकसान पहुंच रहा है। एक तरफ टैरीकाट और टैरीवूल वाले मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ सूती कपड़ा उद्योग को नुकसान हो रहा है। इसलिये समूचे वस्त्र उद्योग का अगर राष्ट्रीयकरण कर लिया जाएगा कहीं घाटा और

कहीं मुनाफा मिल कर ठीक से काम चल सकेगा और इस उद्योग में लगे काफी लोगों को राहत मिलेगी।

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : सभापति जी, कपड़ा उपक्रम विधेयक में दो मुद्दे सामने आये हैं। पहला यह कि लगभग 35 हजार मजदूर हड़ताल के कारण भुखमरी से परेशान थे। और दूसरा यह कि इन 13 मिलों की माली हालत हड़ताल के पहले से ही बहुत खराब थी। जब यह दोनों बातें देखी जाती हैं तो ऐसा लगता है कि आखिर यह 23 महीने इस विधेयक को लाने के लिए और 21 महीने अध्यादेश को लाने के लिए क्यों लगे ? 3, 4 महीने हो गये मजदूर भूखे मर रहे थे, इस सदन में चर्चा हुई। अगर वास्तविक रूप में उसकी चिंता होती तो हो सकता था कि यह विधेयक साल भर पहले आ जाना चाहिये था। और जहां तक माली हालत की बात है खुद सरकार ने कहा है कि हड़ताल के बहुत पहले से इनकी माली हालत खराब थी। फिर आखिर क्या कारण जो इतना समय लगा विधेयक और अध्यादेश को प्रस्तुत करने में ? कुछ इसमें मिलीजुली कुश्ती का एहसास होता है। पहले जमाने में एक हंगेरियन पहलवान आता था कुश्ती लड़ने के लिए जिसका नाम किंगकांग था और भारतीय पहलवान था दारा सिंह। देश के सारे शहरों में उनकी कुश्ती होती थी। कभी कोई जीतता था और कभी कोई। बाद में पता चला कि यह कुश्तियां मिलीजुली चलती थीं। ऐसा लगता है कि 23 महीने के समय में मिलीजुली कुश्ती तो नहीं है ? ऐसी शंका मन में होती है।

इस शंका के कुछ कारण भी हैं ...

एक प्रश्न और आता है कि आखिर इन 13 मिलों का इस प्रकार राष्ट्रीयकरण क्यों किया जा रहा है, 12, या 14 मिलों का क्यों नहीं ? हमारे यहां शास्त्रों में 13 का अंक अशुभ माना जाता है। अब कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां जो अशुभ रहता है, वह शुभ हो जाता है। शायद मंत्री जी ने किसी ज्योतिषी से पूछा होगा उसने 13 का अंक बताया होगा। अहमदाबाद में, बम्बई में 60 मिलें काम कर रही हैं, दर्जनों बीमार मिलें हैं, हमारे इंदौर में भी होपमिल बीमार है। सारे हिन्दुस्तान में 150 मिलें बीमार होने के बाद भी आप 13 मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में निर्णय क्यों ले रहे हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। ये 13 मिल-मालिक कैसे हैं, इस पर भी विचार करना पड़ेगा।

एक मिल-मालिक ऐसा है जिसने मजदूरों का पैसा, प्राविडेंड फंड का पैसा रोककर 6 मर्सीडीज ट्रक और 8 अम्बेसेडर कार खरीदकर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई।

दूसरी कंपनी फिनले है। हिन्दुस्तान में सब जानते है कि उनकी माली हालत क्या है। फिनले के पास मजदूरों का 6 करोड़ रुपया बकाया है। क्या यह 10, 5 महीनों का बकाया है ? बहुत पुराना है एक जमाने से चला आ रहा है, क्योंकि फिनले ने इन मिलों से रुपया निकालकर अन्य कामों में डाला है।

तीसरा एक मिल है जिस पर शासन ने छापा मारा और उस मिल के अंदर 18 एम्बेसेडर कारें उस मालिक की और 40 लाख रु० की चांदी जप्त की गई है।

[श्री बाबूराव परांजपे[

आखिर मजदूरों का श्रमिकों का लाखों करोड़ों रुपया डकारकर इस प्रकार से दुरुपयोग करती हैं। जब हम इन 13 मिलों की बात देखते हैं तो इनमें 10 वे हैं जिन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल करवाई है, क्योंकि सारे आर्थिक अपराधी हैं।

अभी श्री यादव जी ने बात कही कि मिल मालिक हाईकोर्ट में चले गये हैं इस विधेयक के खिलाफ । यह तो मिलीजुली कुश्ती होती है। मैं मध्यप्रदेश का एक्साइज विभाग का उदहारण आपको बताऊंगा।

हमारे मध्यप्रदेश में गलत ढंग से शराब बनाने का कुटीर उद्योग हो गया है, घर-घर, कुटिया-कुटिया शराब बनती है। शराब के बनाने वाले और थाने वाले मिले-जुले रहते हैं। हर महीने थाने का 3,4,5 हजार रुपया बंधा रहता है परंतु इसके बावजूद भी थानेदार को कुछ एक्साइज के केसेज एस० पी० को देने होते हैं वह कुटी उद्योग वालों से कहता है कि आज तुम्हारे यहां रेड होगी। वह कहता है, ठीक है। एक नौकर का नाम, 9 मटकी दारू, कुछ महुआ सड़ा हुआ जप्त किया जाता है और आंकड़े सरकार के पास पहुंच जाते हैं । तो यह मिलीजुली कुश्ती की तरह ही सब समझ में आ रहा है कि 13 मिल मालिकों और शासन के कुछ मठाधीशों के बीच में मिली-जुली कुश्ती हुई। जब 13 मिल मालिकों ने हरी झंडी दी तब आपने अध्यादेश जारी किया, यह चार्ज मैं इस शासन पर लगाना चाहता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : मनगढ़ंत चार्ज है।

श्री बाबूराव परांजपे : राष्ट्रीयकरण का सिद्धांत तो हमने मान लिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : कुल 13 का क्यों ? औरों का क्यों नहीं ?

श्री बाबूराव परांजपे : राष्ट्रीयकरण का सिद्धांत तो हमने मान लिया है कि अच्छा है और आज प्राइवेट सैक्टर में जिस प्रकार से गड़बड़ियां चल रही हैं, उसको देखते हुए मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि सारे कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाय तो बहुत अच्छा हो। परन्तु एक बात समझ में आती है कि टैक्स पेयर कहता है कि सारे उद्योगों में कोई उद्योग या कारखाना निकलता है तो सरकार उसे लेती है तो उसके मन में कंपकपी आती है। तो एक कहावत है—

"जहां जहां पैर पड़े संतों के
वहां वहां बटाधार"

संतों का तात्पर्य हमारे मंत्री जी से नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पजाब के संतों से नहीं है, दिल्ली के संतों से है।

श्री बाबूराव परांजपे : दिल्ली के संतों से भी है।

श्री मूलचन्द डागा : भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीयकरण को मानती है।

श्री बाबूराव परांजपे : श्री रावत ने कल एक बात कही थी। उन्होंने हमारे मंत्री जी को राजनीतिज्ञ संत की संज्ञा दी थी, राजनीतिक संत उसमें लागू नहीं है। मैं जानता हूं कि वह बहुत साफ-सुथरे आदमी हैं। परन्तु आज आम आदमी के

दिमाग में यह बहुत जरूरी है कुछ नौकरशाह और कुछ राजनैतिक मठाधीश मिल कर राष्ट्रीयकरण को बुरी तरह से बदनाम कर रहे है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस तरफ थोड़ा ध्यान दें।

मंत्री महोदय ने 19-10-83 को बम्बई में एक प्रेस कांफरेंस में ब्यान देते हुए कहा था कि 13 मिलों की कीमत लगभग 44 करोड़ रु० आंकी गई है। प्रश्न उठता है कि देने वाली रकमें कौन कौन सी हैं। प्रापर्टी में श्रमिक सब से पहले आते हैं, जिनको 17 करोड़ रुपए देने हैं। वे देने चाहिए। उसके बाद बैंक आदि फिनांशल इंस्टीट्यूशंज आती हैं, जिनका 25 करोड़ रुपया देना है। इन दोनों को मिलाकर 42 करोड़ रुपए की देनदारी है।

इसके अतिरिक्त सप्लायजं को भी 60 करोड़ रुपया देना है, जो कि सिक्युर्ड लोन नहीं होता। ये लोग बड़े आदमी नही होते।

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग के मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मिली-जुली कुश्ती हो रही है, क्या ?

श्री बाबूराव परांजपे : जो छोटी इंडस्ट्री वाले पांच दस मजदूर और टेक्नीशियन रख कर काम करते हैं, उनका 60 रुपया देना है। आंकड़ों के हिसाब से 2 करोड़ रु० बचे हैं। तो इन 60 करोड़ रुपयों का क्या होगा ? मंत्री महोदय यह चिंता कर रहे हैं कि 35,000 मजदूरों को काम मिलना चाहिये, परन्तु जिनको 60 करोड़ रुपए देने हैं, उनके पास भी 35,000 मजदूर काम कर रहे हैं। अगर उनके 60 करोड़ रुपए डूब गए, तो ये 35,000 मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे।

दो मास पहले 13 मिलों को हमने ले लिया। पांच छः मिलें 15, 25 या 50 परसेंट उत्पादन कर रही थीं। परन्तु विगत दो मास से—जब से अध्यादेश लागू किया गया है, तब से—उन 13 मिलों के दरवाजे तो खुले हैं, किन्तु उनमें एक भी मजदूर घुस नहीं रहा है। यहां पर मजदूरों की भलाई की बात हो रही है, परन्तु बम्बई में उल्टा काम चल रहा है और 35, 40 हजार मजदूर बेकार हैं।

मारूति उद्योग जब हस्तांतरित हुआ, तो ऐसेट्स एंड लायबिलिटीज भी हस्तांतरित हुई, जिसका पैसा उसे मिलना चाहिए था। जो 35,000 मजदूर सप्लायजं के छोटे उद्योगों में काम कर रहे हैं, अगर उनको बचाना है, तो उनकी देनदारी का भी विचार करना चाहिए।

शासन के वक्तव्य के अनुसार उनके पास सरप्लस जमीन है, जिसकी कीमत 195 करोड़ रु० आंकी गयी है। हम चाहेंगे कि शासन उस जमीन को बेचकर उस रकम के द्वारा सप्लायर्ज का पैसा दे और मिलों का आधुनिकीकरण करे।

SHRI Y.S. MAHAJAN (Jalgaon): Mr. Chairman, Sir, I rise to congratulate the hon. Minister for Commerce on this Bill to take over the Management of 13 mills in Bombay. It had to be done by an ordinance which was promulgated on the 18th October, 1983. The Government had no option but to go in for the take-over of these mills in the public interest pending their nationalisation.

[Shri Y.S. Mahajan]

Their financial condition was bad even before the long-strike which began in January, 1982. Their mismanagement had resulted in aggregate liabilities of about Rs. 170 crores. Much of their machinery is defective, obsolete or mere junk. They had borrowed heavily from the public financial institutions and, even after the strike was over, they could not absorb the labourers who were in the employment on a permanent basis.

So, in the interest of workers and public financial institutions and, with a view to increase production and distribution of cloth, it was necessary to take over the management of those 13 mills in Bombay.

It is difficult to understand the furore created by this proposal to nationalise the mills among the mill owners in Bombay. They have rushed to the High Court with writ petitions. With their bungling and bad management, they could not rehabilitate the mills at all. To upgrade the machinery, to modernise and reorganise them, it is expected that about Rs. 140 crores would be required during the next four years. To provide such a large amount capital is beyond the capacity of mill owners. What is the amount that they have invested in these mills so far ? Only Rs. 12 crores, a paltry sums as compared with their heavy liabilities of about Rs. 170 crores which they had incurred.

There is really no reason for paying any substantial amount of compensation to these mill owners. They will be paid about Rs. 44 crores out of which Rs. 17 crores will go to the workers,a substantial amount of Rs. 25 crores will go to public financial institutions and the little amount that remains will go the mill owners for taking over the management of mills The rate at which they are going to be paid—the word "compensation is not used in the Bill—is 50 paise per 1000 spindles, Re. 1 for 100 looms and 1 p. for 1000 metres of cloth processed in a processing unit. However, the amount so paid to all the mill owners will not exceed Rs. 30,000 per annum.

This bring us to the real nature of Indian capitalism. It is not characterised by sturdy individualism and risk-bearing, the qualities or virtues, that are attributed to it by its supporters. With a small stake in manufacturing units under their control—how small it is has been revealed recently ; it varies from 2 to 5 per cent,, they borrow heavily from the public financial institutions. They make a lot of illegitimate gains and allow the units to become sick. When the Government nationalises the units in public interest to maintain production and employment, they resent this measure create a lot of furore and rush to the court with writ petitions. It is quite clear that capitalists in this country have no desire to fulfil their social obligations.

AN HON. MEMBER : They are parasites.

SHRI Y.S. MAHAJAN : I am saying it in a different language.

Industrial sickness has become too widespread in our country. In this particular case, the Government should Institute an inquiry to find out how thriving units have been reduced to mere scrap by bad management. The role of vested interest in the exploitation of these mills and in the reduction of their capital to zero should be exposed. Unless strong steps are taken, it will not be possible to arrest the rot that has started in the industrial sector of this country.

The task of modernising and reorganising these mills will not be an easy one. As the financial Memorandum states, Rs. 140 crores will be required to upgrade machinery over a period of four years. The managerial resources of the National Textile Corporation will come under heavy strain and there will be innumerable legal and other difficulties to deal

with, in connection with the labourers who were permanent but who had migrated to other units and want to come back these mills.

In addition, there are general problems of increasing cost and demand recession which the textile industry has cope with, as a result of which the indusry is in a bad shape. We cannot forget the fact that the National Textile Corporation has already accumulated losses to the extent of Rs. 430 crores. These losses are likely to increase in future till the mills under the NTC and these 13 mills are fully modernised and efficiently managed.

15.55 hrs.

(MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*)

There is no doubt that Sections 6 to 13 will help the Government in the difficult process of reorganisation and of meeting or postponing the liabilities arising out of contracts entered into at any time within three years, immediately preceding the day of the take over. Section 6 sub-section (a) is comprehensive in nature and provides that the Government may, by a notification, declare that the Industrial Employment Standing Orders Act, 1956, the Industrial Disputes Act, 1947 and the Minimum Wages Act, 1948, shall not apply or, sha l apply with such modifications to these undertakings, as may be specified by a notification to be issued under this Act.

I would like to make two suggestions as regards the future management of these 13 units. The first is that a serious attempt should be made to involve workers in the management of these mills. This is the declared policy of our Government and also an obligation under the Constitution. The Industrial Policy Resolution, 1956, clearly states that labour is a partner in the common task of development and should participate in it enthusiastically. There should be joint consultation and workers and technicians should, wherever possible, be associated progressively in the management that is in the process of decision-making.

My second suggestion is that the Government should re-organise some of these mills and arrange their production in such a way as to give them export orientation. The cotton textile industry is the biggest organised industry in our country. It accounts for 20% of the total industrial production. It also accounts for 11% of our total exports. Recently we have been losing our position in the textile market. So, special efforts are necessary to increase production for exports to enable us to face competition in foreign markets, from countries like Korea and Taiwan.

With these few remarks, I support both the Ordinance and the Bill brought forward by the Hon. Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Four hours were allotted and we have already exhausted the four hours. There are still two Members from the Opposition and four Members from the ruling party. If every Hon. Member—because this is very small Bill and a very important Bill also—may please take not more than five minutes. We have got to take up supplementary demands and the mid-term Five Year Plan appraisal. Now the time is 4 O'clock.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : I would like to dispose of my points very quickly. Therefore, I will take up the points regarding the Bill itself.

One of the objects of the Ordinance was that the Government is very serious to protect the interests of the workers. I will simply point out two or three clauses from which it will be evident that the real interests of the workers have not been properly protected. Not only that, I feel that the trade union rights guaranteed in the other laws of the country are likely to be overridden by the provisions of this Bill. Let me explain one or two.

[Shri Chitta Basu]

Clause 6(a) reads :

"all or any of the enactments specified in the Second Schedule shall not apply or shall apply with such adaptations, whether by way of modification, addition or omission...to such undertaking as may be specified in such notification",

You claim to have been a trade unionist once. Now, what is the Second Schedule ?

"The Industrial Employment (Standing) Orders) Act, 1946" Any trade unionist knows how important it is for the workers. The Second in the Second Schedule is :

"The Industrial Disputes Act, 1947" The third is :

"The Minimum Wages Act, 1948"

"The Bill says that these Acts, these laws, shall not be applied or may be applied after suitable amendments. Therefore, my first objection is that you are taking away by this provision certain rights which these three laws give to the workers. Further comment on this is not necessary.

Clause 6(b) reads :

"(b) the operation or all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders...shall remain suspended or shall be enforceable subject to such adaptations ..as may be specified in the notification."

That means, the operation of all these may be suspended or may be given effect to after suitable modification, and that modification will be made by the Government. The workers have no right, nor the Parliament or the Legisalture has the right to decide whether these changes are good or bad, legal or illegal, constitutional or unconstitutional. That right, you have usurped for yourselves.

PROF. N.G. RANGA : It will be placed on the Table of the House.

SHRI CHITTA BASU : We know what is the fate of papers laid on the Table of the House. The Table is there and we have got our fate here ; we know the fate.

Another important thing is that "the provisions of this Act or any notification, order or rule made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any law." "*Any* law"; whatever law might be there, the provisions of this legislation shall be applied—notwithstanding the provisions contained in any law in the country.

Yesterday in answer to a question by Shri Indrajit Gupta, you have said that you are not only for take-over but also for nationalisation and 'nationalisation' is not in the very distant future. Now what does this Bill provide ? In Clause 6(2) it is stated that the notification made under sub-section (1) the period of suspension, etc., may extend upto three years.

Will the hon.Minister kindly clarify that by the inclusion of these provisions, you also want to delay the step for actual nationalisation for three years ?

Sir, this has to be clarified. As the Bill provides that this can wait till three years, am I to assume that the actual nationalisation can be considered only after three years ?

SHRI MAGANBHAI BAROT (Ahmedabad) : This is like judicial separation before divorce.

SHRI CHITTA BASU : Look at clause 13. It says :

"If the Custodian is of the opinion that any contract of employment entered into by any textile company or managing or other director of the company in relation to its textile undertaking at any time before the appointed day is in-writing, he or it may, by giving to the employee one month's notice in writing or salary or wages for one month in lieu thereof, terminate such contract of employment."

I do not know what is the fate of it? I have no time though I have enough figures to show...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Keep them for some other day.

SHRI CHITTA BASU : Even for these 35,000 workers, employment is not guaranteed if the House is so pleased to pass this Bill. Therefore, I have got strong reservations about this. I have, for example, pointed out certain instances as to how the interests of the workers are not going to be protected, if this Bill is enacted. This is one point. Therefore, my comment is this. This Bill is welcome so far as the takeover policy decision is concerned. I welcome it. But, my welcome to the Bill is to the extent that it deserves. You do not deserve the full-throtted support from this side of the House. We are very much concerned about the rights and privileges of the workers.

Now, coming to the main issue, the problem cannot be solved unless the entire industry is nationalised. If you will permit me two or three minutes, I point that out. Sir, I have got a report which says about the total picture of the textile industry in our country. I quote :

"An analysis of 32 major textile mills shows that at the end of 1980-81, the total assets of the industry came to Rs. 619.01 crores while net sales reached Rs. 2,507.97 crores. This meant tremendous profits. On the other hand, the production of cloth has been going down. It went down by seven per cent between 1977-78 and 1981-82, for which figures were available. The working strength in weaving went down by as much as 20 per cent. The working group said the fall in production was deliberate and a planned move of sabotage; they wanted to price their commodity at a very high rate to earn maximum profits, curtailing production, paying scant attention to the needs of the common man for this essential commodity."

The whole enquiry or analysis suggests that they are earning profits. The mechanism of profits is by way of cutting down the production. The production has been cut down or has been reduced. I have got the figures.

AN HON. MEMBER : What is your advice ?

SHRI CHITTA BASU : My advice is nationalisation. That is the only way to make it the property of the nation and not that of Tatas, Birlas and others. This is the only advice and this is the only sound and sane advice. The sooner you accept this advice the better it is for the country and better it is for your party also. I have no time. My point is this the actual positition is that the total textile industry is earning profits, That is, they are having their earnings by way of profits by cutting down the production and by raising the prices of the commodity. This is a commodity which is very essential. Now I will quote certain figure. This is from Political and Economic Weekly. It is self-explanatory ; I need not dwell upon it ; the hon. Minister is

[Shri Chitta Basu]

quite capable of understanding it. It says:

> 'Cloth production has been lagging behind plan targets and the per capita availability has also declined.'

Regarding per capita availability I will mention only one figure. The annual average for the last 3 years 1980 to 1983 works out to only 14. 6 metres. In 1964 it was 16.83 metres. Significantly enough, the sixth plan target of 16.59 metres in 1984-85 is lower than the per capita availability in 1964. What is your 6th Plan target ? Only 16.59 metres. Therefore, it means, if the inddustry remains in the hands of persons under whom it is functioning now, the industry cannot produce the total requirement of cloth required by the common man of this country. You want to rob the common man to make the monopoly houses earn more and more profits. They earn big profits at the cost of the common man, at the cost of the public exchequer. What is the alternative ? Only nationalisation. The sooner you decide, the better for our people. You muster enough courage, after you have taken over all these 13 textile mills, to take over the other mills also and subsequently nationalise the entire textile industry. This is what I would plead with the hon. Minister. With these words I conclude.

SHRI R.R. BHOLE (Bombay South Central) :I come from Bombay. I was also elected from Bombay, where the textile workers had gone on strike. They went on strike at the instance of Mr. Datta Samant ; the workers were misled by the lectures of Mr. Datta Samant. He promised workers that he will see that workers get 200 or 300 per cent more of wages; he used to deliver such lecture not once, but several times. He also used to give some wrong figures saying he has obtained so much percentage increase of wages for other industrial workers elsewhere in Greater Bombay and Metropolitan Bombay and the workers fell a prey and followed the wrong precepts of Datta Samant. They just fell in his trap. They were misled not once or twice not for one or two months but for more than 1 1/2 years. We were trying to persuade all concerned here as well as in Bombay that the Mills should be opened immediately. But there were several kinds of difficulties. It is not that all the workers had struck work. Majority of the workers wanted to return after some period, but they were not allowed to return, because they were threatened with dire consequences. In fact, the records show that there were several murders committed on the loyal workers, so many were injured and so many had to be hospitalised. The point is that the loyal workers were threatned, and some were murdered. By whom, that the court will decide. For a long time, for about six months, majority of the workers were not willing to return. I am happy that, though late in my opinion, the Government has now taken over these thirteen mills. I am also happy that the compensation proposed is not exhorbitant as the mill-owners wanted. I would not say it nominal, because the mill-owners with about twelve crores of rupees of investment had already got hundreds of crores of profit in white money.

My friend was saying just now that the production had gone less. But our experience during the course of strike was that the textiles did not become costlier at all. We never felt that they had gone on strike, or that the textiles available in the market were less. The textiles which were accummulated by the mill-owners came in the market through the rear door and that is how, the textile shopwallas were selling the textiles which were hidden and concealed by the mill-owners. And that is the reason, why in Bombay and elsewhere, the textiles did not, become more expensive.

I want to bring pointedly to the notice of the hon. Minister one thing. If this is the conduct of these thirteen mill-owners and if this is also the conduct of the majority of the mill-owners

in Bombay, as well as in Ahmedabad and elsewhere, will you or will you not consider taking over the mills of these bad mill-owners? They are bad because they have not paid crores of rupees of wage bill; they are bad, because they have swallowed the loans advanced by the banks; they are bad because they have swallowed also the loans of the IDBI and other financial institutions.

If this is the conduct of the mill-owners, if they work with only two to five percent of their capital, and work with the capital of the financial institutions and get profit, and a large part of the profit is not shown, and it goes into the black money, will you or will you not nationalise all the textile industries in this country, specially in Bombay ? I plead that the Minister should examine the accounts of the textile owners. It is not very difficult to find out who is who in all these mills. If an enquiry is made, I have no doubt that the hon. Minister and the Government will find out that these mill-owners are bad. They are not running their mills properly. They are mismanaging the whole thing. Therefore, instead of allowing the sick mills to become sick, he must catch hold of them by the scruff of the neck and nationalise as many mills as possible. This is what I wanted to say.

But, at the same time I also want to say that it should not be handed over to the administrators of the N.T.C. We know enough what the N.T.C. has done. I wish the Hon. Minister examines again his own proposal to give or not to give these to the N.T.C. At least give to good people who are competent and who have not mismanaged their mills.

PROF. N.G. RANGA : Again to some other mill-owners.

SHRI R.R. BHOLE : I don't say mill-owners, Sir.

Sir, I also plead that at least one mill he must experiment as a workers' cooperative mill and in the others he must provide full participation of the workers in the management of the mills.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातों की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं। इस सदन में जो अब तक के भाषण हुए हैं। उन से एक बात तो बहुत साफ है कि जो कपड़ा उद्योग की स्थिति इस देश में है वह बहुत दयनीय है आम तौर पर लोग महसूस कर रहे हैं कि इस देश का कपड़ा उद्योग जो सब से बड़ा उद्योग है वह आज बिल्कुल पुराना हो गया है, पचास साल तक की पुरानी मशीनें और पुरानी तकनीक ज्यादातर मिलों में कायम है। जब तक यह स्थिति रहेगी इस देश का कपड़ा उद्योग न तो देश की आवश्यकता को पूरा कर सकता है और न हम दुनिया की किसी प्रतियोगिता में किसी के मुकाबले में आ सकते हैं। आज इस बात की भी संभावना बहुत ज्यादा है कि हिन्दुस्तान दुनिया के बाजार में काफी बड़ा योगदान अपने हथकरघा के कपड़े से, अपने पावरलूम के कपड़े से और मिलों के कपड़े से भी दे सकता है। इस देश में काफी बड़ी परम्परा है अच्छा कपड़ा और अच्छी डिजाइनें बनाने की और हाथ का हुनर जितना इस देश में है उतना दुनिया के कम देशों में है। इसलिए इसकी संभावना बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी पोटेंशियलिटी जिस उद्योग में है उस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

जहां तक एन० टी० सी० का सम्बन्ध है इस वक्त सवा सौ मिलें एन० टी० सी० के पास हो गई हैं। वह एक बहुत बड़ा

[श्री चन्द्रजीत यादव]

संगठन हो गया है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से कम से कम यह आशा की जा सकती है, इन की ईमानदारी पर सब को भरोसा है और यह ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं आज इन से कहना चाहता हूं कि एन० टी० सी० की स्थिति इस समय इस माने में बहुत खराब है कि भ्रष्टाचार वहां बहुत ज्यादा है। आज आप के 25 बड़े अधिकरियों के खिलाफ सी० बी० आई० की जांच हो रही है। आप देखें कि उस की स्थिति क्या है? इस वक्त कोई अगर खींच रहा है तो अधिकारी नहीं बल्कि मजदूर स्वयं इस तरफ ध्यान खींच रहा है। कई जगह स्थिति ऐसी है कि मजदूरों ने खुद भ्रष्टाचार का पता लगाया है, मिलों का घेराव किया है और अफसरों का घेराव किया है। मजदूरों ने सरकार को तथ्य दिए हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। आज मजदूरों में इतनी चेतना आ गई है कि मिलों के उत्पादन की रक्षा करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। इस लिए मजदूरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी मुझसे पहले श्री आर० आर० भोले साहब बोले हैं, जैनुल बशर साहब बोले हैं, उन्होंने भी कहा कि यह कदम बहुत देर में उठाया है और ये आप से अनुरोध कर रहे हैं कि दूसरी मिलों के संबंध में जल्दी से जल्दी कदम उठा लीजिए। जब आप कदम उठायेंगे और फिर उस पर रुपया खर्च करेंगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपको पुनर्स्थापित ही करना है, तो जो एन० टी० सी० की मिलें है, उन पर आपको दो हजार करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर वे मिलें आधुनिक मिलों की स्थिति में आयेंगी। 13 मिलें आपने ली हैं, इसकी जमीन आप बेचेंगे तो आपको 157-158 करोड़ रुपया मिलेगा, उसके अलावा लगभग 150 करोड़ रुपया और लगायेंगे, इस प्रकार 300 करोड़ रुपया खाली इन 13 मिलों को रिहैबिलिटेट करने में खर्च होगा। इस स्थिति से आप स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं।

सारे देश में एक अरब 20 करोड़ वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता है, जिसको हम कहते हैं कि नियंत्रित क्लोथ है। एक अरब बीस करोड़ वर्ग मीटर के खिलाफ 40 करोड़ वर्ग मीटर कपड़ा तैयार हो रहा है। आपने योजना बनाई है कि करीब-करीब 65 करोड़ वर्गमीटर कपड़ा तैयार करना चाहते हैं। आप इसको कैसे तैयार करेंगे? 40 करोड़ तैयार कर रहे हैं और चाहिए एक अरब 20 करोड़, लगभग साढ़े तीन करोड़ गुना, तो इसके लिए आपको मशीनों की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए अच्छी मशीने होनी चाहिए। आपके पास अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि यदि तीन महीने पर आप स्वयं बैठकर मुख्य अधिकारी कुछ मैनेजमेंट के और एन० टी० सी० के, क्वाटरली रिव्यूह कर लिया लीजिए, ताकि आपको स्थिति की जानकारी हो सके। एन० टी० सी० की मिलें जो सूत्र तैयार करती है, उसका करीब-करीब 56 प्रतिशत खुद बुनकर खरीदता है। जो कि हथकरघा उद्योग में लगे हुए हैं। लेकिन सूत की क्वालिटी गिरती जा रही है। उसकी जरूरत का सूत उसको नहीं मिलता है। सूत यदि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में चाहिए तो तमिलनाडु से खरीदना पड़ता है और यदि तमिलनाडु को चाहिए तो अहमदाबाद से

भेजना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है। समय की कमी की वजह से मैं इसकी सारी व्यवस्था पर नहीं जाऊंगा। एन० टी० सी० पर कभी विस्तार से मंत्री महोदय खुद या यहां बहस करवा लें, तो उनको सदस्यों के द्वारा एक अच्छी तस्वीर मालूम हो जाएगी। मैं अपनी बात सीमित रखते हुए, आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एन० टी० सी०, जिनके पास सवा सौ मिलें हैं, के चेयरमैन पार्ट-टाइम चेयरमैन हैं ? क्या यह सच है कि तीन साल से मैनेजिंग डायरेक्टर की परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है, एक ही आदमी दो काम कर रहा है ? यदि इस प्रकार की स्थिति है, तो आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

एक स्वदेशी काटन मिल, दुर्भाग्य से हमारे जिले भौनाथ भजन में भी हैं। यह पिछले करीब तीन साल से घाटे में चल रही है। इन मिलों के पुर्जे निकाल लिए गए हैं। मैनेजमेंट खराब है। इस मिल का एक मजदूर, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, जो कि इस मिल में काम करते हैं, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से मिलकर सारे तथ्य दिए हैं। जिस प्रकार एक्साइज ड्यूटी को बचाने के लिए वहां का मैनेजर सूत को निकालता है। एक्साइज ड्यूटी के अधिकारी ने भी उसकी जांच की है और यह मालूम हो गया है कि यह मैनेजर खुद मिला हुआ है और चोरी कर रहा है। लेकिन आज तक कोई उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्यों ? वहाँ एक दो व्यापारियों के साथ मिलकर उस मिल के सूत को बेचने के नाम पर पैसा कमाया जा रहा है। वे लोग मैनेजर की सांठगांठ से काम कर रहे है। लेकिन कोई कार्यवाही नही की जाती है।

मैं आपसे मांग करता हूं कि आप वहां किसी उच्च अधिकारी को भेजकर उसकी जांच करा लीजिए, लेकिन मैनेजर को हटा कर जांच करवाइयेगा, तभी आपको तथ्यों का पता चलेगा। कहीं तो कदम उठाइए, एक दो उदहारण तो पेश कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि वहां इस प्रकार की बातें हो रही है।

एक जे० के० रेयन है उस को मजदूर घेर कर बैठे हुए हैं। उन का कहना है कि जिस दिन घेराव हटायेंगे मिल-मालिक तीन करोड़ रुपये की मशीनें और पुर्जे निकाल कर बेच देंगे, इस लिये हम घेराव हटाना नहीं चाहते हैं। इस तरह के वाक्ये पहले भी हुए हैं—कुछ उद्योगपतियों ने जब उन को मालूम हो गया कि टेक ओवर होने वाला है मिल के पुर्जे और बढ़िया-बढ़िया मशीनें निकाल कर ले गये। मेरी प्रार्थना यह है कि आप थोड़ा इस के ऊपर ध्यान दीजिये। आप ने इस समय जो कदम उठाया है, वह बहुत अच्छा कदम है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस देश में कपड़ा उद्योग के जितने कारखाने हैं उन सब का राष्ट्रीयकरण कीजिये। उन को स्वयं चलाइये या मजदूरों की कोआपरेटिव्ज को चलाने के लिये दीजिए। कृपा कर इस प्रयोग को शुरू कीजिए। अगर महाराष्ट्र में चीनी की कोआपरेटिव मिलें सफलतापूर्वक चलाई जा सकती हैं तो गुजरात और बम्बई में कपड़ा मिलों को भी कोआपरेटिव्ज के द्वारा चलाया जा सकता है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

दूसरी बात मैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । आप को मालूम है और मेरा अपना खुद का तजुर्बा हैं—मैंने इस्पात के कारखानों में वर्कर्स पार्टिसिपेशन को शुरू किया था और उस का नतीजा यह हुआ था कि एक साल में जो यूटिलाइजेशन केपेसिटी 62 प्रतिशत थी, वह बढ़कर 82 प्रतिशत पर पहुंच गई । वर्कर्स पार्टिसिपेशन से जितना फायदा मिलों की प्रोडक्शन बढ़ाने में हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ था ।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को भी उत्तर प्रदेश की कोआपरेटिव चीनी मिलों का तजुर्बा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : इस लिये मेरा निवेदन है कि आप वर्कर्स पार्टिसिपेशन को शुरू करें ।

इस वक्त आप की 34 काटन मिलें बंद हैं, जिन में तीन ऐसी हैं जिन का पिछले महीने टेक ओवर किया है, बाकी क्यों बंद हैं इस के लिये कदम उठाइये ।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सटाइल मिलों के अधिग्रहण का जो विधेयक इस समय सदन समक्ष प्रस्तुत है, मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । 18 अक्तुबर के दिन बम्बई की 13 मिलों के अधिग्रहण के लिये हमारे मंत्री महोदय ने राष्ट्रपति जी के माध्यम से जो अध्यादेश जारी कराया उस के लिये बधाई के पात्र हैं । यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है—कपड़ा मिलों की स्ट्राइक से देश के उत्पादन को कितना नुकसान हुआ है । जहां 18 महीने की हड़ताल में इस उद्योग के लगभग ढाई लाख मजदूर बेरोजगार हुए, वहां दूसरी ओर इस से देश के उत्पादन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा अनुमान है कि 15-16 सौ करोड़ रु० का नुकसान हुआ । हमारे राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में कुल औद्योगिक उत्पादन का 20 प्रतिशत उत्पादन हमें टैक्सटाइल मिलों के माध्यम से मिलता है, इतना ही नही जो मिलें बाहर अपने माल का निर्यात करती थीं, कुल निर्यात में 20 प्रतिशत की भागेदारी टैक्सटाइल मिलों की होती थी । इन सब के महत्व को देखते हुए जब हमारी सरकार ने 13 मिलों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की तो इस से न केवल देश की जनता को बल्कि उन तमाम मजदूरों को राहत की सांस मिली जो पिछले 18 महीने से बेरोजगार थे । उन का यह निश्चय राष्ट्र के हित में है, बेरोजगारी दूर करने की दिशा में एक ठोस कदम है और राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में बहुत बड़ी उपलब्धि है ।

इस समय 110 टैक्सटाइल मिलें एन० टी० सी० के पास है जिन में सस्ते किस्म के कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है । हमारी सरकार का यह भी प्रयास है कि उस के माध्यम से हमारे आम उपभोक्ता के काम में आने वाला जो कपड़ा है, वह कम से कम दामों में अच्छी क्वालिटी का उसे उपलब्ध करावे पर यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज जो टैक्सटाइल मिलों की दुर्दशा हो गई है जो उन की मशीनें घिसी-पिटी हो गई हैं, उन के आधुनिकीकरण की अत्यंत आवश्यकता है । अगर

इन 13 मिलों की मशीनों की हालत को आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि इन में जो मशीनें हैं, वे 40-50 साल से घिसी-पिटी हालत में चली आ रही हैं और इस कारण की उत्पादन क्षमता घट गई है और अच्छे किस्म का जो कपड़ा बनाने की इन की क्षमता होनी चाहिए, वह नहीं रह गई है और यही कारण है कि क्षमता के मुताबिक उत्पादन नहीं हो रहा है और मजदूरों को मिलों की आय के मुताबिक जो प्रोफिट मिलना चाहिए, वह प्रोफिट उन को नहीं मिल पा रहा है और मिलें दिन ब दिन घाटे में जा रही थी ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी जो कि सार्वजनिक संस्थाओं और हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों का बहुत ज्यादा ऋण उन के ऊपर हो गया और उन्होंने यह उचित समझा कि अब ये मिल प्रारम्भ न किये जाएं। अब जब हमारी सरकार ने इन मिलों को लिया है, तो हम मंत्री जी से यह अपेक्षा करते हैं कि हमारे देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए, हमारे यहां से निर्यात की बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुए, आज इन के नवीनीकरण की आवश्यकता है। हम उन में आधुनिक टेक्नोंलाजी अपनाएं और जो स्पीनिंग, वीविंग और प्रासेसिंग की तकनीक है, जो दुनिया की आधुनिकतम तकनीक हो सकती है, वह अपनाएं। ऐसी मशीनों का निर्माण हमारे देश के टेक्नीशियन हमारे देश की टेक्नोलोजी को विकसित कर के कर सकते हैं और उस टेक्नीक को इन मिलों में अपनाने की आवश्यकता है। इस बिल में मंत्री जी ने दर्शाया है कि इन मशीनों का आधुनिकीकरण करने के लिए अगले 4 वर्ष में 140 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। इस से यह स्पष्ट लगता है कि हमारी सरकार की यह मंशा है कि जिस हालत में हमको ये मिल मिली हैं, उस हालत में आगे हम उन को नहीं चलाना चाहते हैं और हम उन का नवीकरण करना चाहते हैं और हम उन में आधुनिक तकनीक लगाना चाहते हैं और उन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। हम उन में आधुनिक किस्म के कपड़े बनाना चाहते है और उस के उत्पादन में आधुनिक तकनीक को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। यह एक स्वागत-योग्य कदम है और हम आप से यह अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से आप ने इस मिल में विभिन्न उद्देश्यों को रखा है, उस से आने वाले समय में निश्चित लाभ राष्ट्र को मिलेगा।

अन्त में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। योजना का जो प्रारूप इस बिल के माध्यम से इन मिलों के प्रबंध का अधिग्रहण करने का दिया है और भविष्य में जो इन का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि एक अच्छी दिशा आप ने इन कपड़ा मिलों के टेक-ओवर के लिए दी है। मैं मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि जहां इन मिलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, वहीं इन मिलों का सही और सफल संचालन करने की आवश्यकता है क्योंकि एन० टी० सी० के पास 110 मिलें पहले से हैं और अभी 13 मिल ये और हो गई हैं। इस तरह से 123 मिलें इन के पास हो गई हैं मैं यह चाहूंगा कि इन को दो-तीन गुणों में विभक्त कर के कारपोरेशन बना दें जिस से कि इन के मेनेजमेंट की व्यवस्था सुदृढ़ हो और अक्षमता के साथ इन का मेनेजमेंट चल सके। हमारी सरकार का यह अनुभव है कि जहां पर भी बड़ी कम्पनियों का

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

विभाजन किया गया, पेट्रोलियम के क्षेत्र में ऐसा किया है और अब एल० आई० सी० के क्षेत्र में हम ऐसा करने जा रहे हैं और फर्टिला जर्स प्लांट जोकि हमारे देश में विभिन्न जगहों पर कायम थे उन के मामले में भी ऐसा किया गया है, तो वहां के मेनेजमेंट की व्यवस्था में सुधार हुआ है। उन में आपस में कम्पीटीशन हुआ है और उन से लाभ भी बढ़ा है और राष्ट्रीय उत्पादन का महत्व भी बढ़ा है। मेनेजमेंट की दृष्टि से ऐसा हम इस में भी कर सकते हैं और टैक्सटाइल उद्योग को विभिन्न 4-5 ग्रुपों में बांट कर उन का अलग अलग कारपोरेशन बना कर उन की क्षमता और उन के लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से इस का लाभ आने वाले समय में मिलेगा।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य से इन कपड़ा मिलों का अधिग्रहण किया गया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में यह एक पहल है और निश्चित रूप से यह एक स्वागत-योग्य कदम है। यह हमारी प्रधान मंत्री जी की भावना के अनुरूप भी है कि सर्वसाधारण के लिए सस्ता कपड़ा और अच्छे से अच्छा कपड़ा राष्ट्र में निर्मित कर के लोगों को उपलब्ध कराएं।

आप ने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सारी बीमारी की दवा इन्होंने बतलाई है और एक राम-बाण औषधि दी है और वह है राष्ट्रीयकरण, और राष्ट्रीयकरण के कारण आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। ढाई अरब रुपया जो लगा हुआ है, उस की हालत आप जानते हैं और आज भी इस साल 81 करोड़ का घाटा है। और कुछ नहीं घर हमारा बरबाद होने दो और राष्ट्रीयकरण का नारा लगाओ। कांग्रेस ने मिक्सड इकोनामी को माना है। अगर कम्पटीशन होता है और उद्योग अच्छे चलते हैं तो कौन चाहेगा हम लोगों के हाथ में पूंजी रखें? बिना सोचे समझे एक आवाज लगा दी जाती है कि राष्ट्रीयकरण कर दो, चाहे वह बिजली हो, ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी हो सब का राष्ट्रीयकरण कर दो। यह मांग बारबार उधर से लगायी जाती है बिना सोचे समझे। मैंने देखा है 1979 से 81 तक 73 मिलियन डेज का नुकसान हुआ। जो इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीयकरण करना चाहिये, क्या आपको मालूम है एन० टी० सी० में 436 करोड़ का ऐकुमुलेटड लौस है? इस साल भी घाटा है। इलाज यह था, स्टेटमेंट में मंत्री महोदय ने साफ कहा है :

> "According to Mr. V. P. Singh, the Government of India was forced to take over the mills in view of several overwhelming reasons. For one thing, the liabilities of these mills would be far more than their assets. It was improbable that the present owners would get sizable funds to pay off the liabilities and modernise the mills. He said that the Central Government was forced to take over the management of these mills essentially to absorb the workers wishing to resume duty, to ensure optimum utilisation of available infrastructure and to increase production of yarn for decentralised sector and cloth for the common man."

जब उन्होंने यह कदम उठाया, उसकी जब

सराहना होने लगी तो लोग कहने लगे एन० टी० सी० में बड़ा भ्रष्टाचार है। अब बड़े-बड़े भ्रष्ट अफसर भी फंस जायेंगे, हमारे मंत्री जी उत्तर प्रदेश में डाकुओं को मार कर आये हैं अब भ्रष्ठ अधिकारियों को यहां मार देंगे। किसी भ्रष्ट आदमी के यहां आने की हिम्मत नहीं है। इसलिए कुछ दिन बाद ही आप देखेंगे कि एन० टी० सी० में मुनाफा होगा। यहां पूंजीपति और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठगांठ नहीं चल सकेगी। एक आदमी ने मजबूत कदम उठाया 20 महीने बाद और लोग चिल्लाने लगे कि राष्ट्रीयकरण कर दो। 13 मिलें जो हमने ली हैं उस कदम की आप सराहना कीजिये। अगर आज आप लेना चाहते हैं तो लेने के लिए आपके पास साधन होने चाहियें। क्या आपको मालूम है कि आज कितने मिल सिक हैं ? आज 5 लाख मिल सिक हैं, उनमें कितनी पूंजी लगी हुई है ? अरबों की पूंजी लगी हुई है।

एस्टीमेट्स कमेटी की 1982-83 की रिपोर्ट में लिखा है—

> "The Committee find that one of the functions assigned to the Textile Commissioner is to give technical guidance and render advice to the industry in its programme of modernisation and rehabilitation and to recommend financial assistance where required. It transpiced during evidence that the Textile Commissioner had not drawn up even over all plan of action for modernisation. In fact, the Textile Commissioner could not even indicate as to how many mills, out of 228 textile mills to whom soft loan of Rs. 245.39 crores was disbursed till March 1982 had been completely modernised ....

> "There is no in our country as yet by which a textile mill could be forced to invest on modernisation. The licences of mills which refuse or delay modernisation could not be cancelled. There is also at present no prohibition on a textile mill diverting its funds for setting up new industrial undertakings."

मिलें जब बीमार होती हैं तो उस समय तो काम होता नहीं है। यह 13 मिलें कितने सालों से बीमार होने लगीं, पैसा उन्होंने बैंक से ले लिया, घाटा डाल दिया।

जिस दिन ये मिलें ली गई, उस दिन बम्बई में जो हालत हुई है वह सबको मालूम है। इनकी गाड़ियां जप्त हो गई, झोंपड़े जप्त हो गये। वह श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद करते होंगे, कि एक रात को जो धमका हुआ है, वह सारे मिलों को मालूम हो गया कि अगर हमने आधुनिकीकरण नहीं किया तो हमारा भी यही हाल होगा। उनके दिमाग में एक दहशत बैठ गई। यही नहीं, यह एक इशारा है, मि० बारोट ने कहा है, गुजरात वाले सुन लें, यह चेतावनी है, बम्बई में घुस गये हैं, अब गुजरात में घुसने वाले हैं। जहां ये कदम रखेंगे, वहां के व्यापारी आपके पास आयेंगे।

मैं यह खुद मानता हूं कि जो कदम उठ गये हैं, उनकी आप तारीफ कीजिए, यह नहीं कि एडवाइजरी पैनल हर टैक्सटाइल की सैट-अप हो।

> "The Central Advisory Council on the Textile Industry with the Union Commerce Minister as the Chairman, was formed today" It was officially announced on 30th November, 1983.

[श्री मूल चन्द डागा]

जब काम करना शुरू कर दिया तब आप क्या कहना चाहते हैं? हमने काम देरी से किया लेकिन किया तो है। आज पावरलूम और हैंडलूम का कपड़ा देश में कितना है आज वह कम क्यों है? एक तरफ तो आवाज बहुत है कि कीमतें बढ़ गई, मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाओ, आप यह आवाज उठाते हैं और दूसरी तरफ मजदूरों की तनख्वाहें न बढ़ाओं, बोनस न दो तो गड़बड़ और फिर कहते हैं कि कास्ट बढ़ गई। आप दो बातें नहीं कर सकते हैं।

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी भारत सरकार को करोड़ों रुपयों का घाटा इस कारण होता है कि काम करने वाली सरकारी मशीनरी को जिस ईमानदारी और निष्ठा से काम करना चाहिए, वह उससे नहीं कर पाई है। विरोधी पक्ष के सदस्य पहले तो कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण करो और जब पब्लिक अंडरटेकिंग्स के सुधार के लिए कोई कदम उठाया जाता है, तब भी वे हल्ला मचाते हैं कि यह कदम मजदूर-विरोधी है। केवल ये लोग मजदूरों के हितैषी हैं, हम नहीं हैं।

मजदूरों के हित में यह पहला कदम उठाया गया है। जिन 35,000 मजदूरों को अपने गहने और बर्तन बेचने पड़े हैं—श्री भोले बता सकते हैं कि उन लोगों की हालत कितनी दयनीय हो चुकी थी—, अब वे उन तत्वों के चुंगल से निकल सकेंगे और अपनी रोजी कमा सकेंगे।

माननीय सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त, ने इस बिल का फिनांशल मेमोरेंडम नहीं देखा और कहा कि फलां बात नहीं बताई गई है। उसमें डीटेल में बताया गया है कि 140 करोड़ रुपए से मिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और मजदूरों को भुगतान किया जाएगा। लेकिन यह खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीयकरण के पक्ष में बोलने लगी है। वे अपनी नीति के विरुद्ध बात न करें और सी० पी० आई० (एम०) की बातों में न आएं। उन्होंने बंगाल की सारी मिलें बंद कर दी हैं। कहीं मध्य प्रदेश में भी यही हालत न हो जाए। वे उनका अनुकरण न करें।

यह जो कदम उठाया गया है, वह एक सही और मजबूत कदम है और उसका स्वागत तथा समर्थन करना चाहिए। भ्रष्टाचार है, कौन इस बात को नहीं मानता? लेकिन माननीय सदस्य विश्वास रखें कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और भ्रष्टाचार दोनों विरोधी चीजें हैं और दो विरोधी चीजें एक साथ नहीं रह सकतीं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं टैक्सटाइल अंडरटेकिंग्स (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेंट) बिल का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं भाग्यशाली हूं कि जब से इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई है, तब से मैं यहां बैठा हूं और दोनों पक्षों—अपने पक्ष और विपक्ष—के विचारों को सुनता रहा हूं। यह बात साफ हो गई है कि हमारे पक्ष के सदस्यों ने तो तहे-दिल से इस बिल का समर्थन किया ही, विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भी अगर-मगर के साथ इसका समर्थन किया है। हमारे वरिष्ठ सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त, ने

इस टेक ओवर में राजनीति देखी । उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों को देख कर वाणिज्य मंत्री ने इन मिलों का टेक-ओवर किया है। दूसरे साथियों ने भी इसमें कई तरह की बातें देखीं। श्री जटिया ने आर्डिनेंस के निरनुमोदन का प्रस्ताव रखा है, लेकिन उन्होंने भी इस बिल का अनुमोदन किया है।

वाणिज्य मंत्री ने बड़ी दृढ़ता और संकल्प के साथ ऐसे समय में इन तेरह मिलों के प्रबंध को अपने हाथ में लिया है, जबकि दत्ता सामंत के नेतृत्व में हुई हड़ताल के कारण बम्बई की सारी मिलों की हालत बड़ी खराब हो गई है और रुग्ण मिलों की हालत तो और भी खराब हो गई है। मैं इस बिल के उद्देश्यों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि इसके उद्देश्य तो साफ हैं। सरकार ने इन मिलों को सिर्फ इस लिए लिया है कि श्रमिकों का हित हो सके, दूसरे उत्पादन बढ़ सके और तीसरे जो हमारी वित्तीय संस्थाओं का रुपया लिया हुआ है उसकी रक्षा हो सके। टैक्सटाइल मिलों की देश में जो हालत है अभी डागा जी ने कुछ संकेत किया और अभी परसों ही वित्त राज्य मंत्री जी ने राज्यसभा में कहा कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं उन में 180 यूनिट्स ऐसी हैं जो पिछले 6 महीने में 113 करोड़ रुपये का घाटा दे चुकी हैं। यही नहीं, हमारी प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले सप्ताह उन के कार्यक्रम के अन्तर्गत जो उपक्रम हैं उन के प्रति असंतोष व्यक्त किया है।

एक बात जो सभी लोगों ने कही कि एक साथ सभी सूती मिलों का क्यों नहीं राष्ट्रीयकरण हो गया तो उन को देखना चाहिए कि आखिरकार एन० टी० सी० आज 125 मिलों का प्रबंध कर रही है और उस में भी 34 मिलें घाटे में हैं । उस का भी उत्तर अभी पिछले दिनों राज्य मंत्री जी ने राज्य सभा में दिया था । तो इस को ध्यान में रखते हुए यह एक साथ तो नहीं हुआ लेकिन इस में कोई शक नहीं कि राष्ट्रीयकरण की ओर दो कदम और आगे बढ़े हैं। मूल चन्द डागा जी ने ठीक ही कहा कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है तो जो सरकारी संस्थाएं हैं उन में प्रतियोगिता का होना आवश्यक है ताकि उन में भी सुधार हो। इसलिए केवल यह बात कह देने से कि सब का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया, काम नहीं चलने वाला है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उन से जो हमारी मिलों के आफिसर्स हैं उन को भी सीखना चाहिये और अपने यहां भी अच्छा प्रबंध करने का प्रयत्न करना चाहिये।

साथ ही साथ मैं आगाह कर देना चाहता हूं गवर्नमेंट को और वित्त मंत्री जी को कि जिन जिन संस्थाओं में और जहां-जहां प्राइवेट सेक्टर में आप ने अपनी पूंजी लगायी है उस की रक्षा के लिए निश्चित तौर पर आप अपने आदमी भेजिए । नहीं तो अभी आप ने ठीक ही कहा, हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने धमाका दिया है और यह धमाका केवल कपड़ा मिलों के लिए ही नहीं है, यह सरकार की तरफ से धमाका है जिस से सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को चेत जाना चाहिए कि यदि वह सरकारी धन का दुरुपयोग करेंगे तो उन के साथ भी इस तरह की बात हो सकती है । इसलिए

[श्री राम प्यारे पनिका]

यदि उन्होंने किसी मिल के लिए कर्जा लिया है, मिल के अन्दर नयी तकनीक का प्रयोए करने के लिए और उस में सुधार लाने के लिए पैसा लिया है तो उस का प्रयोए उसी काम के लिए होना चाहिए। इस तरह का सीख उन को इस से लेनी चाहिए। लेकिन जो रुग्ण मिले हैं, अभी जैनुल बशर साहब ने कहा कि कोई अस्पताल तो है नहीं सरकार के पास कि जितने बीमार पड़ते जायं उन को ठीक कर के वह उन को देती जाय। अभी बसु साहब ने एक शंका व्यक्त की कि इस में तीन साल की व्यवस्था है। लेकिन उन को मालूम होना चाहिए कि इस बिल में ही यह व्यवस्था है कि हम इस को नेशनलाइज ...(व्यवधान)... उस में तीन साल के बाद नहीं, तीन साल तक है। ऐसा नहीं है कि तीन साल के बाद करेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के कठोर हाथ सभी ने देखे हैं। सभी लोगों को याद होगा कि जब वह मुख्य मंत्री थे तो किस प्रकार से वहां के असामाजिक तत्वों पर प्रहार हुआ और उत्तर प्रदेश में फिर एक शांति आई, मैं चाहता हूं कि उसी कड़ाई और सख्ती के साथ एन० टी० सी० और दूसरे जो आप के अन्तर्गत उपक्रम हैं उन में सुधार लाने की बात आप करें। आप की दक्षता, आप की ईमानदारी और आप की निष्ठा सब को मालूम है। मैं तो यह कहूंगा कि मंत्री जी निस्पृह है, ईमानदार तो आप हैं ही। तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप इस हालत में अवश्य सुधार लाएंगे।

पिछले दिनों साथियों ने बताया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की मिलों में फर्क है। दक्षिण भारत की मिलों में अच्छा उत्पादन हो रहा है, उन में घाटा नहीं है, जब कि उत्तर भारत की जो मिलें हैं, जितना भी घाटा है वह इधर उन में ही हो रहा है, तो उन की भी प्रबंध-व्यवस्था को आप दुरुस्त करने की कृपा करें। आखिर कार हम समाजवादी ढांचे में चल रहे हैं तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो कपड़े की क्वालिटी है अनेक प्रकार की क्वालिटीज हैं। कहा जाता है कि विदेशों के मुकाबले हम अच्छा कपड़ा नही बना पा रहे हैं। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि कंट्रोल क्लोथ के कपड़े की संख्या निश्चित तौर से बढ़ाई जाए। इसको बनाने का काम प्राइवेट मिलों पर भी डालना चाहिए। उनके साथ एक शर्त लगानी चाहिए कि उनको निश्चित मात्रा में इतना कंट्रोल का कपड़ा भी पैदा करना पड़ेगा। जो सब्सिडी कंट्रोल क्लोथ में एन० टी० सी० को दी जाती है, वह उससे उस घाटे को पूरा नहो कर पा रही है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी कंट्रोल का कपड़ा बनाने के लिए दबाव डालना चाहिए।

ज्यादा न कहते हुए मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं। और आशा करता हूं कि उन मिलों में आप नए आधुनिक उपकरण लगाकर अच्छी व्यवस्था कायम करने की और प्रयास करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. DEPUTY SPEAKER : Hon. Member, we have already taken one hour more than the allotted time. Now the Minister will have to reply. He requires at least one hour and all Members are waiting for the reply. They have already expressed their desire...

SHRI GIRDHARI LAL VYAS (Bhilwara)—*rose.*

MR. DEPUTY SPEAKER : On every subject you want to speak. All least, this time, you may not get the opportunity. Therefore, I would only appeal to you...

SHRI GIRDHARI LAL VYAS : Will you not give time ?

MR. DEPUTY SPEAKER : You sit down. Don't threaten me.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS : You have not given me time. Therefore, I am walking out against your judgement.

(Interruptions)

At this stage, Shri Girdhari Lal Vyas left the House.

MR. DEPUTY SPEAKER : He is my good friend.

SHRI R. P. GAEKWAD (Baroda) : Sir, I rise to support this Bill by which the Government is taking over 13 textile mills to give employment to the affected workers. Nationalisation of the textile industry is quite easy to say than actually doing it. This is a big job ahead for the Government.

All the hon. Members from this House are well aware of the economic change that is taking place in this country and I would suggest that this industry should be immediately nationalised without any further loss of time. I definitely welcome and admire the decision taken by the Government to take over these 13 sick mills. But at the same time, I would like to submit my observations that there are other mills in this country which are equally sick and need the financial support which the Government is well aware of. Very recently, I had the opportunity of visiting Hong Kong and Singapore where our textiles goods and that of similar countries are on exhibition. I was very surprised and very happy to see that our textiles were no less attractive than those which were exhibited by other countries. So, why should not we be in a position to compete with these countries in the textile industry.

I would like to bring to the notice of the Minister another thing. Number 13 is supposed to be inauspicious. There are 7 mills sick in Gujarat. 13 and 7 will make a very nice 20 in number. Therefore, I would request on behalf of the Mazdoor Sangh Members and Members of this House that the Government should add these 7 mills in addition to 13 mills which they have already been taken over so that an auspicious beginning can be made in this industry. I have two textile sick mills in my constituency and I had the opportunity of talking to the members of the Mazdoor Maha Jan Office-bearers of this unit. Their request is that these 7 mills from Gujarat may be included in the Bill.

With these words, I thank you for giving me an opportunity.

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय मंत्री जी ने जिन टैक्सटाइलं मिलों का राष्ट्रीयकरण किया है, उस के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

सब से पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जितनी कपास पैदा होती है उस का निर्यात बंद कर दिया जाय, क्योंकि जहां हमारे देश के अन्दर बहुत सी टैक्सटाइल मिलों को कपड़ा बनाने के लिये धागा नहीं मिलता है, दूसरी ओर हमें यह भी देखना है कि जो हमारी इन मिलों का एडमिनिस्ट्रेशन है वह ऐसा होना चाहिये जिन को उस काम की वाकफियत हो।

[श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी]

हमारी बदकिस्मती यह रही है कि हमारे जो कारखाने चल रहे हैं उन में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के अफसरों को लगा दिया जाता है जिन को कोई टैक्नीकल ज्ञान नहीं होता है और जिस की वजह से वे मिलें घाटे में चलती हैं। हमारे विपक्ष के लोगों को भी यही कहना है कि इन मिलों में काम करने वाले मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचना चाहिये और हमारी सरकार भी हमेशा मजदूरों की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा कदम उठाती रही है और इसी लिये बम्बई में मजदूरों की जो हड़ताल 18 महीनों से चली आ रही थी उस को समाप्त कराने में हमारे वाणिज्य मंत्री जी, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी और हमारी प्रधान मंत्री जी ने विशेष प्रयास किया और उसी का यह परिणाम है कि 13 मिलों का नेशनलाइजेशन पर दिया गया है।

ये लोग जो सामने बैठे हैं—ये तो चन्दा इकट्ठा करना जानते हैं। मजदूरों को दिलासा देते हैं कि हम तुम्हारी मांगे सरकार के सामने रख देंगे, लेकिन जब नतीजा कुछ नहीं निकलता, मजदूर चलते-चलते थक जाते हैं तो इन नेताओं को मुंह नहीं लगाते। हमारे डागा साहब ने बंगाल की स्थिति के बारे में बतलाया—वह बिल्कुल ठीक बात है। हमारी सरकार मजदूरों को इन्सान समझती है और इन्सानियत के नाम से काम करती है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देती। आज जिन मिलों का नेशनलाइजेशन हुआ है, कम से कम उन मिलों में काम करने वाले मजदूरों का अब शोषण नहीं होगा। आज स्थिति यह है कि जो कपास पैदा करता है, जो खेत से ला कर मंडियों में बेचता है और उस के बाद मिलें कपास खरीद कर कपड़ा बनाती हैं, जो उस कपास को पैदा करने वाला है वह आज भी नंगा फिरता है उस के तन पर कपड़ा नहीं है। जो मजदूर मिलों में उस कपड़े को बनाता है—वह नंगा फिरता है—उस के पास साधन नहीं है कि वह कपड़े को खरीदकर खुद पहन सके। मेरा अनुरोध है कि उन मजदूरों को मिल का हिस्सेदार बनाया जाय और उन को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाय। इस मुल्क के सरमायेदार गरीबों का शोषण कर के चीजों को खरीद कर जमाखोरी करते हैं, माल को अपने गोदामों में भर कर रखते हैं और वक्त आने पर उस का फायदा उठाते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री थे उन्होंने राज्य के डकैतों का सफाया कर दिया था, मुझे उम्मीद है कि वे इन पूंजीपति डकैतों का भी मुकाबला करेंगे। ताकि जो बड़े-बड़े पूंजीपति आज टैक्सटाइल मिलों के मालिक बने हुए हैं उन को ठीक से काम करने के लिए बाध्य किया जा सके।

हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा—अगर इन मिलों का काम ठीक ढंग से नहीं होगा तो इन सामने बैठने वाले लोगों को यूनियन बनाने, नारे लगाने और लाल झण्डा उठाने का मौका मिलेगा। इस बिल के बारे में जितने भाशण हुए हैं सिर्फ दो-तीन लोगों ने ही इस को क्रिटिसाइज किया है, बाकी सभी सदस्यों ने इस की तारीफ की है और मंत्री महोदय को बधाई दी है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है अभी तक ये मिलें घाटे में चल रही थीं,

अब ये प्राफिट में चलनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 13 मिलों के अधिग्रहण का बिल मंत्री जी लाए है, उस का मैं समर्थन करता हूं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की तरफ देखा जाता है लेकिन गुजरात की तरफ नहीं देखा जाता।

गुजरात की जो 7 मिलें है, वे काफी दिनों से बंद हैं। उन के बंद होने के बाद हम ने सैकड़ों लोगों का नेतृत्व कर के जेल काटी है और आज भी हमारी बात कोई नहीं सुनता है। वहां पर मजदूरों की क्या दशा है। 35 साल से समाजवादी समाज की रचना की बात हम चिल्ला रहे हैं और जिस आदमी को आधी रोटी मिलती थी, उस को आधी रोटी देने का हमने वायदा किया है लेकिन आज वह आधी रोटी भी छीन ली गई है। मैं मास्टर्स मोनोग्राम मिल के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर आज 17 हजार मजदूर बेकार हैं और आप ने अखबारों में पढ़ा होगा कि दीवाली पर, जब कि दूसरे लोग पटाखे छुड़ा रहे थे, वहां पर काम करने वाले मजदूर जब अपने बच्चों को संतोष नही दे सके, तो पूरे परिवार के साथ मजदूर ने जल समाधि ली। इसलिए आप मजदूरों की तरफ भी देखिये। अगर आप उन की तरफ नहीं देखेंगे तो जो समाजवादी समाज की रचना के ढांचे की बात आप कर रहे हैं, वह गलत होगा।

एन० टी० सी० की जो बात है, उस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उस में बहुत घोटाला है। मैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी का सदस्य हूं। मैंने अहमदाबाद में देखा है कि कई पब्लिक अंडरटेकिंग की मिलों ने कपड़े की गांठों पर डेमेज का लेबल लगा दिया और व्यापारियों के साथ मिलकर उस को बहुत कम दामों में बेच दिया। इसी तरह से कोयले की जगह पर पत्थर खरीद लिये जाते हैं और एन० टी० सी० में बहुत गड़बड़ चल रही है। वहां पर अपने ही लोगों को कर्मचारी रख लिया जाता है और मजदूरों के साथ अन्याय किया जाता है। मजदूरों के बारे में जो आश्वासन आप देते हैं, वह खाली आश्वासन ही रह जाता है और उन के लिए कुछ नहीं होता है। इस से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से मंत्री जी ने महाराष्ट्र की मिलों का अधिग्रहण किया है, उसी तरह से गुजरात की 7 मिलों का अधिग्रहण भी जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट करेगी क्योंकि मिल बंद होने से बहुत से मजदूर बेकार बैठे हैं। इन को रोजी देने का काम आप करें।

एक और बात यह कहना चाहता हूं कि ये जो धनी लोग हैं, इन्होंने बहुत से मिलों को सिक यूनिट बना दिया है। ये मशीनरी की चोरी करते हैं, कपड़े की चोरी करते हैं और सूत की चोरी करते हैं और बाद में अपने परिवार के दूसरे सदस्य के नाम पर दूसरी इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं और फिर गवर्नमेंट से सब्सीडी लेते हैं, ऋण लेते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि कोई भी परिवार अगर कोई इंडस्ट्री लगाए तो उन की पूरी जांच करने के बाद उस को सब्सीडी देनी चाहिए, ऋण देना चहिए। जो धनी

[श्री हीरालाल आर॰ परमार]

लोग हैं, वे इस तरह से सरकार की ठगाई करते हैं और मजदूरों की भी ठगाई करते हैं। मास्डंम मोनोग्राम मिल के मालिक ने मजदूरों के साथ ठगाई की है और सरकार की भी ठगाई की है। मजदूरों की 4 महीने की तन्ख्वाह भी नहीं दी गई और मिल बंद कर दी। ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह से ठगाई करते हैं, क्रिमिनल ला के अन्दर मुकदमा चलाना चाहिए और उन को सजा देनी चाहिए। गुजरात के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस को खत्म करना चाहिए और सरकार को जल्दी से जल्दी इन सात मिलों को अपने हाथ में लेना चाहिए।

आप ने दो मिनट का जो मुझे समय दिया है, उस के लिए मैं आप का आभारी हूं और पुन: प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी गुजरात की सात मिलों को अपने हाथ में ले कर मजदूरों को रोटी देने का कष्ट करें।

THE MINISTER OF COMMERCE AND OF THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): I am thankful to the Hon. Members for their support in varying degrees, full as well as partial. My gratitude is full and total and unqualified.

I agree with Hon. Members, including the critics of the Government, that the malaise is general and, therefore, partial solutions will not do. It is time that we go deep into the diagnosis of the malaise, before the endemic disease that we see threatens the entire textile industry. Not only sickness needs to be monitored, but it is high time that advance action is taken and a proper forum, a proper machinery, is created. It is all the more important because this is an industry in which about 20 per cent of our manufacturing activity is performed and included. It is also important because about 20 per cent of our exports constitutes textiles and comes from this sector. It is also important because it supplies the essential need of the common man and it has become more important because a very sizeable section of this industry is now in the public sector.

With this background, before going into details—I will try my best to answer the individual questions also which have been raised—I would like to go to the broader, macro picture of the whole industry which is necessary to understand the situation today.

There are two broad categories in which, I think, we should analyse the problem one is the economic factors which are objective; and the other is the managerial factors which can further be subdivided into problems of the private sector and those of the public sector.

In the economic factors we will have to go into the broblems of raw material, consumer demand, the competition we are facing on the export front, the infrastructural constraints, the investment needs, the role of inter-sectoral proportion in which they should be—powerloom or handloom and also the textiles.

In the managerial sector, so far as the private sector is concerned, the area where every Member has expressed his concern is the flight of capital and the reluctance for re-investment into this sector. At the same time, coming to the public sector, the NTC has been mentioned. Of course, everybody has mentioned about the efficiency and losses, but, I think, we will have to go into the production relationship so far as the public sector is concerned. And many Hon. Members have pointed out that in the production relationship the workers' role has to go up in a big way in the public sector.

This being the broad parameter in which the analyse the whole textile industry, I will make my comments on some of the aspects; I will try to be as short as possible while trying to cover such a big spectrum of the issues of the textile industry.

So far as raw material is concerned, we have cotton apart from the man-made fibre. 75 per cent of our cotton is grown in non-irrigated area. Therefore, the raw material availability of this industry becomes very highly sensitive to weather conditions rains, etc. It is also a fact that, when we analyse this problem, we will have to give our attention to productivity itself and efforts on the productivity front of the raw material of cotton on the one side and also the use of man-made fibre and the proportion of that which can buffer us from the conditions of weather, the fluctuations in the availability of the raw material, to what extent the man-made fibre can buffer, in what mix we should have, on these we will have to have a clear policy and decide.

So far as the consumer demand is concerned, this also becomes very highly sensitive, our farmers, the rural sector, being the big consumers of cloth and based on drought, flood or the economic conditions of the consumers. So, on raw material side as well as on the consumer side, this short of situation is there, and we have to look, so far as demand is concerned, on the overall economy, how we can stimulate the whole economy so that it can take care of the demand.

Now, on the export front, concern has been expressed my Mr. Mahajan and also Mr. Yadavji. Sir, it is an irony that India, being one of the largest producers of cotton, perhaps next to China, and very well geographically placed so far as markets are concerned, compared to other countries which are competing, that is, Taiwan, Hong Kong etc.—we are better geographically placed and nearer compared to these countries and also our labour costs are lower, yet, we are being out-priced in the export market. The problem in this sector is, of course, certainly of modernisation of units. Now they have shuttleless looms which produce a larger variety of counts than the conventional looms we have and then the productivity is also high. Also there are certain technical things we have to take care of on the research side which is not there now. Then there is the problem of infra-structure, as I have already said, on the export front. Our whole industry is organised on the basis of price. It is a low-priced economy in which lower priced cotton is in demand and the industry is very sensitive to the price structure, especially in the domestic market while the export market is quality-sensitive and we can get better prices if the quality is maintained. The domestic market is sensitive to price, as that is the state of our economic condition and we cannot be oblivious of this. With this problem in hand, modernisation has to be taken up. An assessment made sometime ago put the cost of modernisation of our textile industry at about Rs. 2000 crores. Now certainly that assessment must have gone up higher. And against the proposed requirement of Rs, 2000 crores, the IDBI had a scheme of soft loan and of this soft loan we could carve out only Rs. 360 crores for modernisation.

Now, when it comes to this and that is the challenges we will have to meet and if we want to do that, we will have to carve out from the national economy a dose of resources for this industry. I am not talking about the ownerships. I will come to that later on. For the whole industry, whether nationalised or partly nationalised or in the private sector, this is the requirement we want; and where will these resources come from ? Now, in the overall national economy, when the resources allocated comes, difficulty arises whether to make the cut in the power or to make it in the irrigation sector or in which sector to make it in the overall general economy. Secondly, apart from the budgetary support, what measures we should take to see that surpluses are

[Shri Vishwanath Pratap Singh]

created out of the industry for reinvestment and how much there is possibility of saving. At the same time, although there is creation of savings, there have been savings and that too good savings, they were not ploughed back or reinvested. How to ensure that they are invested back into the industry ? That is the second problem.

With modernisation it is not an easy task. While the necessity is there because modern machines are labour-displacing as well as raw material-saving, it needs a careful consideration. Now in the past we have taken and I believe in this country, in any model of growth we may take, it will not have political stability unless it is income-distribution and employment oriented. At the same time, while we are all for modernisation, we will have to take care of our socio-economic conditions and within these conditions, how to do it—that is the challenge. But we should not shy away just by quoting this side or that side and say that we will not face it. We will have to take care of the workers; we cannot abandon them. At the same time, we have to modernise. And then in the raw material modernisation, the grower gets affected.

When the raw material, that is cotton or any raw material, becomes lesser, then, we will have to think along with modernisation on how to develop the export markets or, alternatively what to do with the cotton growers. Simultaneously, at this time, the backward linkage with the growers and the forward linkages with the commonman, that is, the consummer, will also have to be taken care of.

Well, we are short of resources. We are seeing this. Everybody knows that our export markets are sealed. Unless we modernise the Mills, we will be out of the market and we will have to pay a price to put it in the market. On the home sector, when we are short of capital, I think the capacity utilisation is a more economic and more cheap method of getting more out of the same investment rather than to go for further doses of whatever we can extract. Better utilisation of capacity, infrastructure and other things that the industry gets should make it comfortable.

Shri Zainul Basher mentioned about having a balanced view of intersectoral relationship with the handloom, power-loom and the organised sector. We will have to be very clear as to what we are going to do with the weaving sector ; much of the weaving sector is decentralised. I am not talking here of handloom. In the power loom sector also we want a weaving sector. But it is very difficult in the organised sector to maintain the weaving sector as a healthy sector. This is a problem. If we take the policy option to maintain the weaving sector in the organised sector, we will have to keep it healthy. There is a vast interest of our organised workers. So, we will have to devise a policy where, by in the weaving sector at least, some buffering of undue competition by avoidance of duties or whatever—is there has also to be taken care of. That has also been pointed out by some one. This will lead us to the tax structure, policy etc. I am not going into them in details. That will take a much more time. In fact we have to fashion our tax structure according to the needs of the problems that we have. These are economic aspects. The objective conditions, the validity of total ownership or partial ownership in the socialistic society and the economic condition are all to be taken care of. I think we will have to pay attention so as to bring the textile industry back to its health. Coming to the management side or ownership side of it, from the private sector we have started this industry. If we have to have a mixed economy, when there is a private sector also, we will have to assure generation of investible things. Thereafter we will have to ensure that if it is textile or jute,

whatever savings we have we do not fritter that away or siphon that away but we try to reinvest that into the jute and textile industries. Already new industries come up.

Chemical industry is there electronics industries are there. This pressure will always be there from these industries to divert or siphon off money and put it there. When this is there, we will have to take measures whereby this can be stopped or, at least, there is a compulsory ploughing back of the money into that so as to make it as a check on it. Many hon. Members have raised very valid points. I do not think that anybody would be in disagreement with these points. But, some sort of mechanism will have to be devised. I want to say as to why these mills were taken over about which Government has been criticised on various grounds. And some have gone also to the other extreme by saying that the mills which are dieing should be allowed to die a natural death. Capital should not be allowed to be bound to an unprofitable area. Productivity of capital should be ensured by allowing it to flow into areas where it is of more production use. I am happy no one in this House has subscribed to these views. Therefore, I feel strengthened by the support of the hon. Member. I express my gratitude to them because there is a strong lobby which used the press and editorials in this respect. These people live in ivory towers divorced from the socio-economic reality. Workers is not a bank draft which can be just made into a cheque and posted into a post office and appear with the investment of a capitalist that he wants to invest anywhere. That mobility is not with the worker. This is one of the reason we want for nationalisation of these mills.

At the same time much of public investment was there and to bring to health more investment was needed and for these reasons we had to take this action because it is not only that capital employs labour, the labour also employs capital. So who employs whom is a thing which is not that the worker is only a worker and not employer of the capital. So, we have to take care of him.

Sir, it was also one of the perceptions of the Government that human element is not a disposable element and those who think it disposable will find one of their citadels torn off one day becouse so long as hunger is there within the stomach it can be quenched with food but when this hunger goes to the mind then it cannot be quenched with food and even your statutes are burnt to the ashes: So, before this stage comes these people should get rid of their mind of such query.

Sir, very practical suggestions have been made by the hon. Members that huge sums of money of financial institutions are put in. Over a period of time imperceptibly—I agree with Shri Indrajit Gupta's view that it is not overnight that some industry becomes sick and one fine morning we see in the newspapers that it is closed due to either an attack of cold or flu—it happens and I recognise that there is need for strong monitoring and coordination with the financial institutions and the administrative Ministry of Commerce to set-up a cell to take effective action in this regard. There is a nucleaus monitoring cell but I assure the House that we will strengthen the cell and use the most modern methods—be it computerisation—to keep a track on these mills. We will also link-up with the banks and create a cell for such monitoring. It has become a dire necessity because what is coming up on the monitoring screen with the rudimentary methods that we have is not very happy. It is something which causes much concern and I share the anxiety of the hon. Members in this respect.

Now, a word about the condition in which some of these mills were left. To show the dimension of mismanagement in these 13 mills not only the workers were

[Shri Vishwanath Pratap Singh]

kept idle but also the looms were idle, operating losses even before the strike were heavy and working capital was negative. Sir, these 13 mills were sanctioned assistance for modernisation. Seven out of these thirteen mills were sanctioned the money but wer unable to utilise even the sanctioned money. Jam Manufacturing, loom capacity idle was about 34 per cent. New City of Bombay Manufacturing Mill, loom capacity idle was abou 88 per cent. Podar Mills, about 88 per cent. I am taking the percentage of loom capacity that was idle. Tata Mills 100 per cent. Elephinstone about 45.3 per cent. Shree Sitaram Mills 100 per cent. Madhusudhan Mills 100 per cent. Finlay, about 90 per cent. Gold Mohar about 89 per cent. Kohinoor 100 per cent. Their operating losses for the year ending 1981 were all negative. I will not go into the figures. Even in 1982 they were all negative. Their working capital in 1982 is all negative. And then one hon. member made this point. The original fund, their own fund, was 12.73 crores and accumulated losses were about 105 crores. The total liability of these mills comes to about 186 crores and the amount that will be needed for modernisation works out to 140 crores.

MR. DEPUTY SPEAKER : Have you ascertained how long these mills have been sick ?

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat) : And, Sir, what is the definition of sickness ?

MR. DEPUTY SPEAKER : That is right.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : This 'sickness' is a matter I have gone into, Sir. It is sub-judice, Sir. What I have said is the preliminary assessment which the NTC has taken. We have nothing to conceal on this count and I wanted to share this information with hon. members to show that we have nothing to hide or conceal on this count. I am saying this only to reiterate what the hon. Members have said, and their concern. There is a need. There is a dire need for it. We had to take action in advance and monitor. That advance action has to be taken. I assure you that we are creating this cell in the Commerce Ministry ; we will strengthen it to make it a functioning cell, to look into, to monitor, to take advance action in coordination with the other financial institutions. This suggestion, with all humility, I accept and I assure you that it will be enforced.

Coming to the management of the public sector and the NTC, here we will have to go into the relationship within the public sector. We have tried an experiment of taking over and putting an officer in charge. We have got very good officers ; they have done very good work and I am proud of the work of some of these officers which they have performed. But it is also a question of the system, what we are evolving. Now we have the profit mechanism. In that respect there is the millowner. He has a right under the present law to earn a profit. For that profit he is there on the spot of the mill and he has an interest in running it. Now it becomes sick. We operate that part. We take out and substitute an officer. Now we have good officers ; so long as he is committed, he does it. He does the work. But we forget that apart from that, there is one section of people which is interested in running the mills and that is the worker. The worker may want DA, the worker may want some holiday ; he may want some holiday ; he may want anything ; but he does not want the closing of the mills. Here is a group of persons, having vested interest, in the running of the mills, and that is the worker. And it is this main spring which we should use on the spot at the mill. Many hon. Members have spoken about this point in order to improve the machinery of the NTC Mills and I am convinced on this count. In Ahmedabad itself, I have

had that experience. Though at subsidiary level, we have labour representatives, but at unit level, we had only upto the floor shop level. But in Jehangir Mill Ahmedabad, we created a management committee of seven, and out of seven, we put in two workers representatives, and it is not from INTUC union ; it is a non-INTUC Union. One, we have taken from the INTUC union. It was done, so that it may not look a governmental showpiece. We have put two workers representatives and I am glad to report the experience as a result of the workers participation, that within three months, they could reduce the waste, increase the spindle utilisation from 7 to 8%. The mill was running on three boilers, the workers themselves suggested that one boiler should be closed, and they could run on with two. They gave us a saving of Rs. 1.25 lakhs per month, and the workers also suggested or agreed even to retrenchment or rationalisation of 27-28 workers there.

With this freedback, I have decided that within one year, we will adopt this at least in one-third of the NTC Mills, and having gained the experience will extend it to the entire NTC.

The other is the question with regard to result--orientation : the people who are incharge of NTC mills should be result-oriented. For this, we are going to make an yearly assessment. I have made it clear, though there has been a criticism in the press, that we will make an assessment of running of a mill over a period of one year, and if a manager of a mill does not perform well, inspite of giving modernisation doses, in spite of providing of machines, and giving all the the allowances for the power cut which is there in some States, or some undue external conditions, he will have to go. Of course, I will not compare their performanc with the private sector, but their own benchmark. If from their own bench mark, their performance falls short of what it should be, that manager will have no place in NTC and will have to find a place somewhere else. We cannot filter away funds of these units like that. As I said, we will implement that after making an assessment......

SHRI MAGANBHAI BAROT : We will fully support you in that.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : Then, a question was raised about the NTC Chairman's appointment pending for three years. A part-time Chairman is already there, and part-time does not mean that he is temporary. We have part-time Chairmen in various corporations. And, then we have an M.D. looking after the affairs. Selection of the next M.D. has also been made by the PSIB and is with the Government for approval ; that is, of course, a procedural matter. And it is not three years, M.D. was there, and he is still there.

Though I have made certain comments about ourselves, and the functioning of the NTC, it should not be taken as an occasion for the glee of the private sector. Private sector should not forget that every NTC mill is a symbol of their failure ; it is a gift which the private sector has given to us as a great symbol of their management inefficiency. And it is from junk that we started ; it is not that we started a new mill, and then came to loss ; we started from losses.

Having said this, I want to tell you that the spindle capacity in NTC is 15.6%. I am not taking the present Bombay mills figures, because I have got the figures of pre-Bombay mills.

In the NTC we have got 23% looms of the industry. Now, I take production in the NTC. Compared to the total production in the textile industry it has 15.6 per cent in the field of spindles and 13.04% in the yarn production. It is true that it is little less, but it should not be forgotten that in 1980 itself 228 million kg of man-made fibre and blended

[Shri Vishwanath Pratap Singh]

yarn was produced in the private sector. We don't have its production in the NTC mills. If we give allowance for this, then the percentage of production in the NTC is no less than the production in the private sector. With 23% of loomage in the NTC, it has a total cloth production 22.46%. So, on the production side the picture is not as bleak as has been painted.

Now if we compare the number of workers employed per thousand spindles in the NTC, you will notice that we are having 33.70 workers per thousand spindles whereas in the private sector it is 27.80. So, we are employing much more.

PROF. N.G. RANGA : Do we pay better wages to them?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : There has been no strike in the N.T.C. for wages. This shows the satisfaction of the workers.

No, I take the average count. It has gone up in the NTC mills. If we compare 1975-76 with 1982-83, in the NTC average count has gone up by 23%.

In regard to the productivity level achieved, if we take per spindle gram conversion, it has gone up by 16% in the seven years. Whereas the loom productivity in 1975-76 was 211, it has gone up to 216. Market yarn production has gone up by 30%, cloth yarn production has gone up by 23%. And the net percentage loss to the production value in the nationalised mills, which was 15.6% during 1982-83, has come down to 6.4 per cent in August 1983. But this includes the moratorium given on the interest charge.

A point was made that contolled cloth production obligation was removed by this Government. I think my hon. friends are very conveniently forgetting that it was in October 1978 that this obligation was removed.

I assure you that in the NTC there is no loss on account of the production of controlled cloth. A case is being made out that the private sector was absolved of it. But we see an excise has been levied on the private sector in lieu of the production of the controlled cloth.

About the blended cloth, a suggestion was made by an Hon. Member. I may inform him that we have started polyester blending for a cheaper cloth of that variety.

Prof. Ranga and others asked about the losses. It is true that they amount to Rs. 425 crores but they are the accumulated losses incurred from the beginning. Moreover, some mills were closed for seven to nine years before we took cover.

I may inform that out of Rs. 425 crores at least Rs. 220 crores have been paid back to the Government. Apart from that within this period, this organisation has paid Rs. 1,377 crores to its labourers as wages. So, keeping this in view we can say that it is serving a useful purpose. Of course, it has got its problems and improvements are also necessary. It was asked what we were going to do about these 22 mills. Perhaps Mr Chitta Basu asked it, or my hon. friends here did it. Not that they are going to be closed. But these 22 mills constitute a very high percentage of the loss of 103 mills which we have got.

SHRI CHITTA BASU : I hope you are not going to close them down.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : We are going to constitute a committee to go into it, and identify what steps should be taken to bring them back to health ; and what further steps we should take. A scare has been created

that they are going to be immediately closed down.

SHRI CHITTA BASU : Can you assure us that they will not be finally closed down? You can take other measures.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : I can give an assurance that we will do everything to keep them open.

A point was raised about funds for modernization of the mills in the South and those in the North. Yesterday it was said that the House should be informed about this aspect. I should compliment the subsidiaries in the South; they are doing very good work. But to say that the mills in the North have been given more of modernization funds, and those in the South less, is not carrect. The subsidiary of NTC in Tamil Nadu and Pondicherry has been given Rs. 47.68 crores; NTC Andhra Pradesh and Kerala Rs. 39.42 crores; NTC South Maharashtra has been given Rs. 38.1 crores-these are the highest. And the lowest amounts given are to NTC DFR Rs. 22.88 crores; NTC U.P. Rs. 22.17 crores and NTC Madhya Pradesh Rs. 27.80 crores. They fall in the lowest range. NTC Gujarat has got a fair dose of Rs. 50 crores. These are the figures they had asked for. So, I have given them.

Now, a question about the delay was asked. A political reason is ascribed for the delay. It is said that because the AICC meeting was there it was done all of a sudden. It is not so. We were on this issue.

SHRI R. R. BHOLE : What about trying to run a mill on cooperative basis?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : On the question of labour in management, I expressed myself quite strongly. I don't think there is any further elaboration needed. Wherever possibilities for it are open, it will be there; i.e. involving more and more of labour in management will be the policy we will be adopting in NTC.

Now, about the reasons for the delay, I need not go into them again. But what was happening already? I remember that many more—more than 13—mills were closed. A few months back, I remember in January or February, we took all steps to revive them.

17.50 hrs.

(DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI *in the Chair*)

Whatever arrangements were necessary from banking institutions—in that respect we took steps. And they were revived. About HRA for labour, the Deshpande Committee report was there. Government immediately accepted it, and took steps for labour welfare. I need not go into the details of it. But it is known that employees drawing about Rs. 750/- per month were given Rs. 32/-; those getting Rs. 751/- p.m. and above were given Rs. 45/- p.m.; those getting wages above Rs. 1250/- were given Rs. 65/- p.m. So, we took care—on the labour side.

But the labour was also coming to the mill-gate. There was no question of the strike existing. It was a reversal of the strike. Workers were coming to the mill-gate and going back. When this stage came, this was the condition : Workers are coming to the mill gate and going back—it is not a condition of strike. How can we be just silent spectators? Government had to act and that was the reason behind it. Stalemate does not make a change. If an action is valid on one day, it is valid for all days; if it is not valid for any day, it is not valid for any day. So, just making a date out of AICC session is not proper. I suppose the more concern is to make politics out of it. Many people want to exploit this political soil; that soil has gone away by

[Shri Vishwanath Pratap Singh]

take over; and they are now more concerned about saying that Congress has done it, has made a political capital out of it.

AN HON. MEMBER : Dirty Politics.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : What is dirty about politics ? If politics were of that dirty, would we be all here ? Is it not politics in anything else than doing what is in public interest. Is it not politics expressing public will; is not politics change of the *status-quo:* is not politics changing of the economic situation and transforming it into something; and if it is so, we are for politics. What is politics about it ? What is wrong about it ? We are all in politics and politics is made for this. Is it your concern that the party will do all wrong things and then go to the electorates ? We will do correct things and go to the electorates. What is wrong in it ?

Yesterday, Shri Jagpal Singh was saying about it and today mili-bhagat theory was also being proposed that we have acted in the interest of big guns. Now, taking over of Podar Mills, Tata Mills, Finlay Mills, Gold Mohar Mills, Jam Manufacturing Mills, Kohinoor Mills and Shree Sitaram Mills is it happening in favour of the guns ? If they were so happy in the mili-bhagat, that is government has done this to oblige them, why have they gone to the court ? They should have said, thank you to us, very nice, you have done this.

A point had been raised yesterday about compensation and it was pointed out that compensation for take over had not been expressed in detail. The detail is given in the financial memorandum itself.—Rs. 30,000 per annum, that is Rs. 2,500 per month for 7 lakh spindles and 12 1/2,000 looms. I will not say that it is less, because that is what they are saying in the court; it is enough and right; it is not excessive.

Shri Ashfaq Hussain said something about giving priority to the workers regarding compensation. I think the NTC has worked out a rough estimate; and it is a rough estimate subject to revision. But the first picture I want to share with the house and that is that the book value of fixed and current assets of these mills come to roughly Rs. 51.29 crores; I am leaving out the decimal so that we can understand it. Rs. 51 crores are the total assets in the preliminary rough assessment that has come, according to the study made by NTC. For this assesment, we will go by the book; for income tax, they go by the books; for us how will they take the land ? What has come and what is there real and correct and what they say that we are doing. Now a question was raised what will the workers get, previous dues; and whether mills owners will make a big profit and government has done something to give them a big compensation; big or small, due compensation is due compensation, according to the law. I do not want to make comments on the facts which are emerging.

I am informed that under the liabilities in respect of sick textile undertakings nationalised in 1974 during the pre-take over management period, priority was like this. Arrears in relation to provident fund, salaries and wages and other amounts due to employees, then secured loans, then revenue taxes, then cess rates or any other dues to the Central Government, State Government, local authority, and then comes any credit availed of for the purpose of trade or the manufacturing operations, then 'any other' etc. Now, out of the amount the secured loans of banks and other financial institutions come to Rs. 115 crores, and then of workers Rs. 20 crores; out of the amount of the time of nationalisation, first will go Rs. 20.26 crores to workers.

SHRI MAGANBHAI BAROT : *Pro. rata* or total ?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : Total. In pre-takeover first

comes the worker. Out of the amount first the dues to the worker will go.

SHRI MAGANBHAI BAROT : I would like to know, supposing Rs. 20 crores are of labours, whether it will all to go to the worker, or *pro-rata* of that amount.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : All the Rs. 20 crores will go to the worker.

SHRI MAGANBHAI BAROT : Thank you.

SHRI SATYANARAYAN JATIYA (Ujjain) : What about the provident fund ?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : That is included. Provident fund, salary, wages and all other amounts due to him are included. Then whatever is the balance will go to financial institutions and banks, that is Rs. 115 crores. Now, whatever is less I am legally ready to give. I am not legally denying anyone. But the law is like this. That is what is coming first in the picture.

AN HON. MEMBER : If you do not have it you do not give.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : I do not deny anybody's due. According to law, whatever is due I will give. I am not vindictive.

Then, one suggestion was made about the sale of land and use of it, for this purpose. I do not want to make any comment. There is no particular proposal as yet before us. The matters are *sub judice*. I do not want to make any comment. The Press has come out that the Government has taken over these mills, saying that land is worth Rs. 160 crores and to sell it for party funds and to generate it for party funds. I think it is motivated news by the vested interests to malign the action of the Government.

(*Interruptions*)

No. It is not on that side. It is not on that side.

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं जानना चाहता हूं कि इंदौर टैक्सटाइल मिल के बंद होने से पहले मध्यप्रदेश सरकार ने कुछ लैंड अलाट की । यह किस कारण से अलाट की यह संशय पैदा करता है । इसलिए ये सारी बात पूछी जा रही है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अभी जो इनफरमेशन है वह मैं बता रहा हूं ।

At least, I may tell you that sale to private persons is not going to be made. So, that rules out speculation in the market; or any underhand dealings. Public sector to public sector is a different affair. For any need that can be done. But at least that is ruled out at this moment.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : We can see tomorrow.

(*Interruptions*)

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : I requested the Chair to permit me to continue for fifteen minutes more.

Now to make it short, about the taken-over and closed mill of Gujarat, a point was made that the Government was not doing anything. There have been other closed units also, which have all been taken over. Three units in Kerala, one in Karnataka and one in Gujarat, all were nationalised by the respective State Governments. In Orissa also one textile mill has been nationalised by the Government of Orissa through an Ordinance,

[Shri Vishwanath Pratap Singh]

by acquiring the mandatorily owned shares in August 1983.

The Government of Gujarat has already submitted the Bills seeking nationalisation of two taken-over mills to the Ministry of Home Affairs for administrative approval of the Central Government. The Governments of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka are being requested to bring necessary legislations as early as possible.

About the Anglo French Mills—Mr. Indrajit Gupta has come at the right time—we are having today detailed discussions with the IDBI. Just after this debate I am going there. The Governor of Pondicherry has also come. I am informed that the solution is very near. I hope a satisfactory solution will come out.

About Gujarat the position is like this. The Mills are Manakchowk, Mahalakhia, Masbin, Monogram, Maharana and PG Textile Mills. Four units are in stages of liquidation. About Maharana Mills a writ has been filed in the High Court of Gujarat. We are in dialogue with IDBI in all these matters and we are trying to work out a package obout the rehabilitation of these mills so that there is some solution of opening of these mills. We are in active dialogue in all these matters. (*Interruptions*)

There are 34 mills and if I talk about each and every mill it will take quite a long time. I have got the material with me. But I can generally say that we will make all efforts and try to bring about solutions for opening and running of these mills.

SHRI ERA MOHAN (Coimbatore) : What about Coimbatore Mills ? The workers are suffering.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : I understand the problem and share your concern.

18.07 hrs.

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

In the JK Rayon we have ordered investigation under the IDR Act. But they have gone to the court and taken stay against investigation.

In the end I say that the Government will continue to give its fullest attention to this industry which involves lakhs and lakhs of workers and give them fruitful employment. The industry is in crisis. We take it as a challenge—a challenge to put it not only on a sound footing but also to give the workers fruitful employment.

With these words, I commend the Bill to the House.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो इस बारे में उदार हैं। मजदूरों के बारे में आज उदार होने की बात कही गई है।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : उधार नहीं नकद है।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैंने उदार कहा है, उधार नहीं। मैं इस बात का स्वागत करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने मानिटरिंग की व्यवस्था के बारे में कहा है। उसकी सारी व्यवस्था वे करेंगे और मिलों को घाटे में होने से बचायेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मिलों को कोल और एनर्जी की सप्लाई ठीक नहीं होती। कोल और एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। कोल के और एनर्जी के न मिलने से सारा प्रोसेस रुक जाता है। एक्सपोर्ट के बारे में भी आपने कहा है। आपको पता होगा कि ताईवान और दक्षिण कोरिया हमसे एक्सपोर्ट में आगे हैं। कई

गुना आगे है। छोटे देश आगे निकल सकते हैं तो हमारा जो इतना बड़ा देश है जो रा मैटीरियल से भरा पूरा है अगर इस में दृढ़ संकल्प हम कर लें तो हम उन सभी देशों से आगे निकल सकते हैं।

राष्ट्रीयकरण के नाम पर यदि सरकारीकरण आप करते हैं, अफसरीकरण करते हैं तो मिलों को लाभ नहीं होगा। एन० टी० सी० का अनुभव हमारे सामने है। अफसरों के भरोसे आपने एन० टी० सी० द्वारा चलाई जा रही मिलों को छोड़ दिया है। इससे बात नहीं बनेगी। आप एक्सपर्ट्स के भरोसे उनको छोड़ें। अफसरों के भरोसे छोड़ेंगे तो आपकी जो मंशा है वह पूरी नहीं होगी। मैं इस बात का हामी हूं कि उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा श्रमिकीकरण होना चाहिये। इससे उत्पादन बढ़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा वर्कर्ज पार्टिसिपेशन हो इसको आपको देखना चाहिए। मजदूरों के साथ आप बहुत सहानुभूति रखते हैं यह आपने कहा है। तब आप वर्कर्ज को सीधे मिलों को चलाने को क्यों नहीं देते हैं। आप के निदेश पर मिलें चलती है। अधिकारी जो हैं वे सारा काम करते है। लेकिन मजदूर जो मिलों में काम करते हैं उनको मिलों का मालिक क्यों नहीं बनाया जाता है। उनको अधिकार दे दें, उनको मालिक बना दे तो वे और भी ज्यादा मेहनत और परिश्रम से काम कर सकते हैं, मिलों को एफिशेंटली चला सकते है जिससे देश की बेहतरी हो सकती है। मजदूरों को उनके हक मिलने चाहिये। जो कमाते हैं, जो मिलों को चलाते है वही मिलों के सच्चे मालिक हैं, यह मजदूरों को एहसास दिलाया जाना चाहिये। यह नया प्रयोग नहीं है। दुनिया में यह प्रयोग हो रहा है। यूगोस्लाविया में मजदूरों के भरोसे सब मिलें चलती है। वही उनके मालिक होते हैं। वहां वे मालिक हो सकते हैं, वहां वे चला सकते है तो हमारे देश में क्यों नहीं ऐसा ही हो सकता है। इस तरफ आप ध्यान दें।

आपने बहुत सी बातों का उत्तर देने का प्रयास किया है। कुछ बातें शायद आपकी नजर से निकल गई है। पी० एफ० के बारे में आप बड़े चिंतित है। आपने कहा है कि मजदूरों का जो हिसाब है उसको आप देखेंगे। बाकी भी जो सरकारी मिलें जिन में मिलों ने पी०एफ० का पैसा जमा नहीं किया है या और भी जहां कहीं जमा नहीं हुआ है, वह जमा हो, इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये। भविष्य निधि की रकम ऐसा न हो कि जमा न हो और उनके भविष्य को अंधकार में डाल दे। इसकी आप पक्की व्यवस्था करें कि भविष्य निधि का पैसा उनके खाते में जमा हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

मजदूरों की बेहतरी के लिए आपने ई० एस० आई० को चलाया है। उनके वास्ते आप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करते है। लेकिन वहां आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं है। उनको आप मजबूत करें। वहां सुविधायें प्रदान करें। सी० जी० एच० एस० की व्यवस्था भी आप किस तरह से चलाते हैं, इसको भी आप देखें। मजदूरों के वास्ते पर्याप्त चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिये।

उनके वास्ते आवास की व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए। आज वह ठीक नहीं है। मजबूरी में कहीं पर रहने के लिए उनको बाध्य होना पड़ता है। मजदूरों को आप

[श्री सत्य नारायण जटिया]

मजबूर मत मानिये । पर्याप्त आवास व्यवस्था आप उनके लिए उपलब्ध करायें ।

जब मजदूर भुखमरी के किनारे पर आकर खड़े हो गए थे उसके बाद आपने बम्बई की मिलों की हड़ताल के बाद इन मिलो को टेक ओवर किया । मजदूरों के हित में किया, यह आपका कहना है । मैं पूछना चाहता हूं कि मजदूरों को भुखमरी के कगार पर ला कर खड़ा करने के लिए क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है ? आपका नाम विश्वनाथ है । सारे मजदूर अनाथ हो गए थे । उसके बाद विश्वनाथ की नजर उन पर पड़ी । ऐसा कैसे हुआ कि मजदूर जब बेकार हो गए, बेबस हो गए, लाचार हो गए, सारी बाजी लगा चुके तब जा कर आप उनका भला करने की समझ आयी । आपको चाहिये था कि समय पर मजदूर की मदद करने के लिए आप आगे आते । यह स्थिति आप पैदा ही न होने देते । यह हो सकता है कि राजनीतिक कारणों से आपने ऐसा किया है । लेकिन मानवता और नैतिक आधार पर सारी बात बहुत पहले आपको कर देनी चाहिये थी ।

(Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी मैं अपनी बात नहीं कह पाया था । मंत्री जी ने जो अच्छी बातें कहीं हैं उनका मैं स्वागत करता हूं । लेकिम कुछ बातें जो की जानी चाहिये वह मैं बता रहा हूं । श्रमिकों के बारे में, मिलों के आधुनिकीकरण, तथा एन० टी० सी० का जो सरकारीकरण हो रहा है उसको रोकिये । आपने कहा है सारी बातों को देखेंगे, अच्छी बात है। कोई भी अच्छा कदम यदि आप उठाते हैं तो हम आपके साथ हैं । लेनिन अच्छी बात के लिए अच्छे संकल्प और विश्वास की आवश्यकता है ।

मैंने अपने भाषण में इंदौर की होप टैक्सटाइल मिल कैसे "होपलेस" की गयी के बारे में जिक्र किया था, वह मिल कई महीने से बंद है, मध्य प्रदेश सरकार ने जो किया वह लोगों को मालूम है, उस मिल के बंद होने से हजारों मजदूर और उनके परिवार के लोग परेशान है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि उस मिल को कब तक आप चला रहे हैं यह बताइये ? हजारों लोग उनके खुलने की प्रतीक्षा कर रहे है । आप मजदूरों की सहकारी संस्था बनाकर उसको देना चाहते है या क्या करने वाले है इस बारे में बता दीजिए ।

उपदेश देना तो सरल है, लकिन उसका पालन करवाना बड़ा कठिन है । हमारा कहना है कि अध्यादेश का तरीका ठीक नहीं है । आप कहेंगे कि हमें समय नहीं मिला । लेकिन यह काम आप पिछले सत्र में कर सकते थे अगस्त महीने में । लेकिन ऐसा नहीं किया । कांच के मकान में रह कर पत्थरबाजी करना ठीक नहीं होता । आप जो कह रहे है कि इसमें राजनीतिक कोई बात नहीं है यह तो समय आने पर लोग ही बतायेंगे । हमें जनता के हित में काम करना चाहिये । अध्यादेश के माध्यम से जो कार्य किया गया उसी के कारण हमारा विरोध है । अच्छी बात भी समय पर न की जाय तो ठीक नहीं होती । संसद के माध्यम से विधेयक आना चाहिये था, न कि अध्या-

देश इस सिद्धांत की अवमानना के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए मैं अध्यादेश का निरनुमोदन करता हूं। साथ ही मंत्री जी यह बतायें कि होप टैक्सटाइल मिल के बारे में सरकार क्या करना चाहती है यह भी मंत्री जी बता दें।

MR. DEPUTY SPEAKER : I shall now put the Statutory Resolution to the vote of the House. The question is :

"This House disapproves of the Textile Undertakings (Taking over of Management) Ordinance, 1983 (Ordinance No. 10 of 1983) promulgated by the President on the 18th October, 1983."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the question is :

"That the Bill to provide for the taking over in the public interest of the management of the textile undertakings of the companies specified in the First Schedule pending nationalisation of such undertakings and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER : The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : There are no amendments to Clause 2. The question is :

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3—**Management of certain textile undertaking to vest in the Central Government**

THE MINISTER OF COMMERCE AND OF THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : I beg to move :

Page 2, line 37,-

for "booklets" *substitute* "book debts". (9)

MR. DEPUTY SPEAKER The question is :

Page 2, line 37,-

for "booklets" *subsititute* "book debts"

Amendment No. 9 was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That Clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : There are no amendments to Clauses 4 and 5. I put both the clause together to the vote of the House. The question is :

"That Clauses 4 and 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

Clause 6—**Power of the Central Govt. to make certain declarations in relation to certain textile undertakings.**

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : I beg to move ;

Page 6, —

for line 6, *substitute*-

"nationalisation of the mills or the expiry of three years from the commencement of this Act, whichever is earlier". (1)

MR. DEPUTY SPEAKER : I put amendment No. 1 to Clause 6 moved by Shri Sudhir Giri to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That Clause 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : There is no amendment to Clause 7, The question is :

"That Clause 7 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8—**Application of Act 1 of 1956**

SHRI SUDHIR GIRI ; I beg to move :

Page 6, lines 41 and 42,—

omit "unless approved by the Central Government" (2)

Page 6, line 45,—

omit "except with the consent of the Central Government". (3)

MR. DEPUTY SPEAKER : I put amendments 2 and 3 to Clause 8 moved by Shri Sudhir Giri to the vote of the House.

Amendments Nos. 2 and 3 were put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Maganbhai Barot, do you want to move your amendment ?

SHRI MAGANBHAI BAROT : I am not moving, but I want to press the Minister. . . . .

MR. DEPUTY SPEAKER : If you are not moving, you cannot press. Now the question is :

"That Clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Caluse 8 was added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : There are no amendments to Clauses 9 to 11. The question is :

"That Clauses 9 to 11 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 9 to 11 were added to the Bill.

Clause 12—**Avidance of voluntray transfers**

SHRI SUDHIR GIRI : I beg to move :

Page 7, line 45,—

for "six months" *substitute* "one year" (4)

MR. DEPUTY SPEAKER : I put amendment No. 4 to Clause 12 moved by

Shri Sudhir Giri to the vote of the House.

Amendment No. 4 was put negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That Clause 12 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Clause 13—**Power to terminate contracts of employment**

SHRI SUDHIR GIRI : I beg to move :

Page 8,—

after line 6, *insert*—

"Provided that if an employee, not working in the executive capacity has been in employment of the company for not less than one year, he shall not lose his job." (5)

MR. DEPUTY SPEAKER : I put amendment No. 5 to clause 13 moved by Shri Sudhir Giri to the vote of the House.

Amendment No. 5 was put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That Clause 13 stand part of the Bill".

The motion was adepted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 **Penalties**

SHRI SUDHIR GIRI : I beg to move :

Page 8, line 21,—

for "two" *substitute* "five" (6)

Page 8, line 22,—

for "ten" *substitute* "fifty', (7)

MR. DEPUTY SPEAKER : I put amendments Nos. 6 and 7 to Clause 14 moved by Shri Sudhir Giri to the vote of the House.

Amendments Nos. 6 and 7 were put and negative.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is that Clause 14 stand part of the Bill

The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : There are no amendments to clauses 15 to 17.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That Clauses 15 to 17 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 15 to 17 were added to the Bill

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the First Schedule and the Second Schedule stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That Clause 1, Enacting Formula, Preamble and Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, Enacting Formula, Preamble and Title were added to the Bill.

THE MINISTER OF COMMERCE AND OF THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : Sir, I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed".

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill, as amended, be passed."

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, Sir, I wish to congratulate myself on having such an efficient and honest Minister who has the courage to turn round to some of our friends and then say, "To be in politics is to do an honest job and to serve the people with integrity", in the manner in which the Minister himself has been serving us. He has anticipated me in one very important respect.

All these mills have become sick because of some defect in the Governmental system that we had till now. We have had the Company Law administration and several other institutions which were expected to watch how the joint stock companies are being managed and the industries with which they are dealing. Unfortunately, they have not done their duty. And what is more, the Government also have not taken up its responsibility seriously enough to go on watching how each one of these industries is being managed by its management. I am glad that my hon. friend, the Minister has taken up this responsibility in right earnest and he is going to create a cell. It is indeed a move of which all of us ought to be proud and all of us should be happy about it.

Secondly, I wish there had been no need at all for this ordinance. Ordinarily we should not resort to these ordinances. It is quite possible that if Government had not come forward with this ordinance, those managements would have played some mischief on coming to know through their own means of information that Government was going to legislate in this manner. And, therefore, there was and there could be some justification for taking those people by surprise through this ordinance. But ordinarily, we should try our best to keep our own secret with ourselves and deal with these matters in the usual legislative manner, taking the House into confidence and seeking their cooperation in getting such legislation passed.

I also wish that our workers have been wiser in Bombay and had not gone through that terrible ordeal of more than $1\frac{1}{2}$ years of strike. Throughout that period, my heart was bleeding and I did not know how to contain my own resentment about this kind of social system in which workers should be obliged to be on strike for more than one year and go through all those sufferings and yet there was no redress at all. The Government was helpless and we were all helpless and I hope the trade-union leaders on one side and the industriatists on the other would try their best to be more cooperative and more humanitarian in their approach towards industrial problems and cooperate with the Government and help it to see that such strikes do not take place hereafter. I need not say anything more.

I would like my hon. friend to warn the Law Ministry to be more industrious, more vigilant and more helpful in prepa-

ring these Bills in such a way that there would not be so much scope for mere rule making power and then placing those rules on the Table of the House and expecting our members to go through all those rules and see which one of them is right, which one of them is extra-legal and so on and so forth. As far as possible, it should be the duty of every Ministry, with the cooperation of the Law Ministry, to see that the Bills which are placed before us are as complete as possible and, to the minimum possible extent, room is left for ruling-making power.

I need not say anything more. I wish to congratulate the hon. Minister for having taking the House into his confidence and assuring us that this Government is really genuine and honest in its profession of friendship and comradeship with our workers.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, though this is a welcome measure, that the hon. Minister has taken over management of these 13 miles, he could have done the same thing for other mills also, as my hon. friends, Mr. Jatiya and Mr. Barot have explained about Indore and Ahmedabad mills. The Government has got the authority to take over the management of these mills also. But I do not know why the hon. Minister did not think of taking over the management of these mills also where the workers are starving and they are not getting their salary. These mills also are facing clousure. This kind of a proposal is there already. The workers are being exploited at various places.

So far as the sincerity of the Government is concerned, I am not talking of the hon. Minister—there is no doubt about him that he it an honest person and he is trying to do his level best—but about the place where he is, I do not think there is any meaning of honesty...

MR. DEPUTY SPEAKER : You were also there for some time. Therefore, don't criticise that.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : Is he sure where he is ?

MR. DEPUTY SPEAKER : You are living in a glass house, Therefore, you must not throw stones on others.

SHRI HARIKESH BAHADUR : My house is made of steel fibre.

What I want to say is that the Government is not sympathetic towards the problem of workers because, when the hon. Minister came as the Commerce Minister here, before that, the textile strike was not properly handled by the Government of the ruling party and most of the workers were suppressed. There had been a lot of exploitation of workers. Their demands were not probably considered. We know how much harassment was created by the Government for the workers. But, anyway, the Government perhaps wanted some political advantage of it and, therefore, they decided to take over these 13 mills. But still they did not nationalise them. My demand is that the mills which are being taken over by the Government must be nationalised. The Swadeshi Cotton Mills should also be nationalised. There in ademand that this industry must be nationalised. Only taking over the management af the mills for six months or a year will not do. There has been a constant demand in this House that there should be nationalisation of this industry. The nationalisation of the industry is not bening done. The workers are also demanding it. I would like to demand from the Government that the Swadeshi Cotton Mills must be nationalised. There has been a lot of exploitation of the workers. If the management is again handed over to the capitalists, the mill owners, the whole purpose will be lost.

Generally, we find that whenever the Government takes over a mill, after modernising it and creating a better situation there, they again hand over it to the mill owners. It is a very bad thing ; it is a very bad practice. It has always been opposed here. I demand that this

[Shri Harikesh Bahadur]

industry must be nationalised. At the same time, the management of Indore and Ahmedabad mills should also be taken over.

The last point which I would like to raise is that workers. must be given participation in the management and it is the most essential factor.

First of all, the Swadeshi Cotton Mills should be nationalised and next workers must be given participation in the management.

These are the two specific demands and I think the Hon. Minister will consider them.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : As regards workers' participation. I said the Government is in agreement for increasing the role of the workers participation.

As regards Swadeshi Mills, that was taken over and the Government has reiterated its stand that the take-over was correct and the matter is in the court and we are fighting it in the court.

As regards Indore and Ahmedabad, I said that we had a dialogue with the IDBI and their packet and see what possible things could come.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill as amended be passed".

The motion was adopted.

SUPPLEMENTARY DEMANDS* FOR GRANTS (GENERAL)

MR. DEPUTY SPEAKER : Now the House will take up Supplementary Demands for Grants.

I am told by the Government that we are very much behind the schedule in our legislative business and the Speaker is good enough to have all discussions, whatever you unanimously say. Therefore, you must all kindly cooperate. This is supplementary demand. The time allotted is only 2 hours Therefore, we will complete it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PATTABHI RAMA RAO) : Before the discussion starts, I have a statement to make.

The current batch of Supplementary Demands includes a provision of Rs. 22.9 crores for loans to Delhi Transport Corporation under Demand No. 80.

It has been stated in the write-up that that the revision of fare structure of DTC is still under consideration of Government.

I have now been informed by the Ministry of Shipping and Transport that the Ministry has decided, *for the present* not to revise the DTC fares. The Hon. Members may kindly take note of this.

MR. DEPUTY SPEAKER : We shall now take up discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 1983-84.

Motion moved : "That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1984 in respect of the following demands entered in the second column thereof.

Demand Nos. 6, 9, 11, 12, 17, 25, 27, 29, 30, 39, 43, 45, 48, 49, 51, 58, 62, 63, 70, 76, 79, 80, 82, 83, 86, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 108, and 109."

*Moved with the recommendation of the President.